सत्यमेव जयते

विस्तृत कार्यवाही: स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन: किसी को पीछे न छोड़ते हुए ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना'

15 -16 सितंबर 2022, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ

Panchayati Raj

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

विषयसूची

क. उद्घाटन सत्र 2

ख. सत्र I स्मार्ट ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी 5

ग. सत्र II- कुशल आईसीटी जनशक्ति 13

घ. सत्र III- स्मार्ट ऊर्जा 15

ङ. सत्र IV- स्मार्ट कृषि और स्मार्ट पर्यावरण 19

च. सत्र V - स्मार्ट स्वास्थ्य 24

छ. सत्र VI- पूर्वोत्तर क्षेत्र उन्मुखी दृष्टिकोण 27

ज. सम्मेलन से प्राप्त मुख्य तथ्य 31

अनुबंध I- 'स्मार्ट ग्राम पंचायतें : ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना; लीविंग नो वन बिहाइंड' सम्मेलन: मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम 32

अनुबंध-II राष्ट्रीय सम्मेलन में मोडरेटर और वक्ताओं की संक्षिप्त रूपरेखा 38

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

भारत के माननीय प्रधान मंत्री के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को साकार करने में, स्मार्ट गांवों को डिजाइन और निर्माण करने की आवश्यकता है जो जमीनी स्तर पर सेवा और रोजगार प्रदान करने में स्वतंत्र हैं। इस संदर्भ में "स्मार्ट ग्राम पंचायत: ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण; 15 और 16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 'लीविंग नो वन बिहाइंड' का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम और वक्ताओं की प्रोफाइल क्रमशः **अनुबंध I** और **II** में देखा जा सकता है।

पहला दिन (15 सितंबर, 2022)

क. उद्घाटन सत्र

स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की शुरुआत सम्मेलन के सभी प्रतिभागियों द्वारा माननीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री सहित गणमान्य व्यक्तियों के गर्मजोशी से स्वागत के साथ हुई।

गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के बाद पंचायती राज मंत्रालय के सचिव द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। अपने संबोधन के दौरान, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने भारत के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया। स्मार्ट गांव ऐसे स्थान हैं जहां ग्रामीण समुदाय सशक्त हैं और उन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए पहल कर रहे हैं जिनका वे सामना करते हैं। डिजिटलीकरण परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है - जब तक कि इसे ग्रामीण संदर्भ में अनुकूलित किया जाता है और ग्रामीण समुदायों की भागीदारी के साथ लागू किया जाता है।

सचिव, एमओपीआर के स्वागत भाषण के बाद, शिक्षा और स्वास्थ्य में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली 2 संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ क्रमशः बायजू और मेडीबडी के प्रतिनिधियों द्वारा की गईं।

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

अपने उद्घाटन भाषण के दौरान, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, शिक्षा और स्थानीय व्यापार के अवसरों को सक्षम करती है, स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करती है, लोकतांत्रिक जुड़ाव को बढ़ाती है और ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव के निवासियों की समग्र वृद्धि करती है। "स्मार्ट विलेज" ग्राम समुदाय के लिए दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण कल्याण गतिविधि प्रदान करेगा जो स्थानीय शासन प्रक्रियाओं में बढ़ी हुई भागीदारी को सक्षम और सशक्त बनाएगा, उद्यमिता को बढ़ावा देगा और अधिक लचीला समुदायों का निर्माण करेगा। माननीय मंत्री ने ग्रामीण नागरिकों की मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जो न केवल सशक्त ग्रामीण समुदायों का निर्माण करेगा, बल्कि स्मार्ट ग्राम पंचायतों को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इस प्रकार, सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को गाँव के नागरिकों के साथ प्रमुख शिक्षाओं का व्यापक प्रसार करना चाहिए।

इसके बाद, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने अपना संबोधन दिया और ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों द्वारा इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया, राज्य / केंद्र सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि निर्वाचित प्रतिनिधि; स्थायी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, पंचायत पदाधिकारियों और ग्रामीण नागरिकों को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने के लिए अपनी ग्राम पंचायतों का नेतृत्व करने के लिए लोगों की आंतरिक इच्छा को जानबूझकर बढ़ावा दिया जाए। यह ई-गवर्नेंस के लाभों को पर्याप्त रूप से स्थापित करके किया जा सकता है जैसे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं, पारदर्शिता में वृद्धि, अधिक सुविधा, राजस्व वृद्धि, और/या लागत में कमी। पेरिंजनम ग्राम पंचायत, केरल

और ओदंथुरई ग्राम पंचायत, तमिलनाडु जैसी कई ग्राम पंचायतें हैं, जिन्होंने अक्षय ऊर्जा पर राजस्व मॉडल सफलतापूर्वक विकसित किए हैं, जो देश के पंचायती राज संस्थानों के लिए उदाहरण के रूप में काम करते हैं। आगे जाकर, पंचायतों के पास आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित होकर और समावेशी विकास, विकेन्द्रीकृत प्रशासन, सुशासन के साथ-साथ एसडीजी 2030 एजेंडा को प्राप्त करने की दिशा में ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देकर जमीनी स्तर पर स्थानीय शासन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

इसके बाद माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में अपना उद्घाटन भाषण दिया। प्रारंभ में, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने में पंचायती राज मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उत्तर प्रदेश राज्य में 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और इस प्रकार देश के ग्रामीण परिवर्तन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। हाल ही में, उत्तर प्रदेश राज्य ने एक ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने प्रयासों की शुरुआत की है, और ग्राम पंचायतों से प्रौद्योगिकी संचालित ग्रामीण परिवर्तन लाकर इस उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान देने की उम्मीद है। हालाँकि, ग्राम पंचायतों के लिए प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर बनना महत्वपूर्ण है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समाधान, अनुप्रयोग और सेवाएं, स्मार्ट कृषि, स्मार्ट जल प्रबंधन, स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे अन्य सभी डोमेन के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकी समाधानों का एक अभिन्न अंग हैं। उत्तर प्रदेश सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति कर रहा है और टेलीमेडिसिन देश के दूर-दराज के कोनों में विशेष स्वास्थ्य सेवा लाने में मदद कर सकता है। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालयों के निर्माण, बैंकिंग संवाददाता सखी या बीसी सखी की उपस्थिति जैसे कदम सुनिश्चित करके सशक्त बनाया जा रहा है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को 233 सेवाएं प्रदान करने का अधिकार दिया जा रहा है और वे समग्र जीपीडीपी के निर्माण में भी भाग ले रही हैं, साथ ही ई-ग्रामस्वराज पीएफएमएस भुगतान इंटरफेस का उपयोग करके भुगतान भी

कर रही हैं। उद्घाटन सत्र का समापन धन्यवाद ज्ञापन और गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह भेंट के साथ हुआ।

ख. सत्र I स्मार्ट ग्राम पंचायत कनेक्टिविटी

स्मार्ट ग्राम पंचायतों और कनेक्टिविटी पर सत्र का संचालन श्री अमरजीत सिन्हा, पूर्व सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज द्वारा किया गया। श्री सिन्हा ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि एक स्मार्ट ग्राम पंचायत को एक पंचायत के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करती है, सूचना प्रसार को सक्षम बनाती है, आय के साधनों के विकास की सुविधा प्रदान करती है और ग्रामीण नागरिकों के लिए पूर्ति की भावना को बढ़ावा देती है। स्मार्ट ग्राम पंचायतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए, यह और भी महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायतें महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि उनमें घर की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती है।

(i) **एकीकृत स्थानीय शासन प्रबंधन प्रणाली (आईएलजीएमएस), केरल:** केरल के आईएलजीएमएस पर प्रस्तुति श्री विनोद कुमार के., पंचायती राज विभाग, केरल द्वारा की गई थी। आईएलजीएमएस को ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने और एक उत्तरदायी स्थानीय शासन ढांचे को विकसित करके सेवा वितरण में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित किया गया है। यह प्रणाली ऑनलाइन रीयल टाइम फाइल स्टेटस ट्रैकिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और कहीं से भी आसान पहुंच जैसी सुविधाओं के साथ एक स्थानीय शासन प्रणाली का निर्माण करके सेवा वितरण में अनिश्चितता और गैर-स्पष्टता जैसी चुनौतियों का समाधान करती है। आईएलजीएमएस सरल और पारदर्शी प्रक्रियाओं का एक मंच प्रदान करता है जो व्यवहार में अवधारणा को आसान बनाने को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार, आईएलजीएमएस सबसे वंचितों सहित प्रणाली तक समान अवसर और पहुंच सुनिश्चित करता है।

(ii) **ग्राम प्रधान, भरतपुर ग्राम पंचायत, टप्पल ब्लॉक, अलीगढ़ जिला द्वारा अनुभव साझा करना:** सुश्री नीलम, ग्राम प्रधान, भरतपुर ग्राम पंचायत और श्री धनंजय जायसवाल, जिला पंचायती राज अधिकारी अलीगढ़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें ग्राम सचिवालय का विकास, हाई स्पीड वाईफाई के माध्यम से सक्षम ईकामर्स सुविधाएं, सक्षम कंप्यूटर, सीसीटीवी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना, पंचायत पुस्तकालय का विकास, बच्चों के अनुकूल हाथ धोने की प्रणाली और बच्चों के अनुकूल शौचालय आदि का विकास शामिल हैं। इस गांव में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन और वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई है। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र और निपटाया जाता है। गांव के बाहर जैविक खाद भी तैयार की जाती है। आरआरसी शेड बनाए गए हैं। वर्मी कम्पोस्ट पिट यानी केंचुआ द्वारा जैविक खाद तैयार करने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं। फिल्टर कक्षों को गाद एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सर्वे में छूटे परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। धार्मिक स्थलों, स्कूलों, पंचायत भवनों, आंगनबाडी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, चौराहों और दीवारों पर स्वच्छता से संबंधित पेंटिंग बनाई जा रही हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस ग्राम पंचायतों के हस्तक्षेप ने अलीगढ़ जिले की अन्य ग्राम पंचायतों को प्रेरित किया है और अन्य ग्राम पंचायतों ने इनमें से कई पहलों को दोहराया है।

(iii) **मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद - मेरठ द्वारा अनुभव साझा करना:** श्री शशांक चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला परिषद, मेरठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मेरठ जिले में 350 से अधिक ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, जो पंचायत भवनों के खाली बैठक हॉल में बनाए गए हैं. इन पुस्तकालयों तक नाममात्र की फीस देकर पहुँचा जा सकता है, जो पुस्तकालय के लिए गंभीर पैट्रन सुनिश्चित करता है और पंचायतों के राजस्व के अपने स्रोत में योगदान देता है। आधारशिला कार्यक्रम के तहत, स्कूलों में ज्ञान केंद्र/ नॉलेज सेंटर बनाए गए हैं, जहां काम करने वाले मॉडल जो वैज्ञानिक अवधारणाओं को उजागर करते हैं, उनको रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच विकसित करना है।

(iv) **डॉ शोभा आनंद रेड्डी, ओएसडी, भारतीय प्रशासनिक फैलोशिप, आरडी और पीआर विभाग, कर्नाटक द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी पहल, कर्नाटक:** कर्नाटक राज्य के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालयों को पुनर्जीवित करने के लिए कर्नाटक की पहल पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। वर्ष 2019 में, इन स्थानीय पुस्तकालयों की निगरानी में स्थानीय निरीक्षण प्रदान करने के लिए 5000 से अधिक ग्रामीण सार्वजनिक पुस्तकालयों को आरडी और पीआर विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस पहल का स्वामित्व सभी के पास है, और तेजी से, पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पुस्तकालयों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अपने सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीण पुस्तकालयों को चरणों में पुनरुद्धार

के लिए लिया गया। कई ग्राम पंचायतों को नए स्थान दिए गए, और कुछ को नए भवन मिले। अधिकांश पुस्तकालयों में बिजली के कनेक्शन, बुक रैक, फर्नीचर, पढ़ने के कमरे या बालकनी, छात्रों के लिए अध्ययन डेस्क, कुर्सी और वरिष्ठों के लिए बगीचे की बेंचें मिलीं। पुस्तकालय भवनों की दीवारों पर आकर्षक भित्ति चित्र बनाए गए थे। पुस्तकालय विभाग, कर्नाटक की डिजिटल लाइब्रेरी में 2,50,11,312 पंजीकृत सदस्य और 21,80,638 ई-कंटेंट हैं। डिजिटल होने का विभाग का निर्णय फरवरी, 2020 में पहली डिजिटल लाइब्रेरी के उद्घाटन के साथ साकार हो गया। दो वर्षों की अवधि के भीतर, कर्नाटक के तहत 372 सार्वजनिक पुस्तकालयों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल पुस्तकालयों में बदल दिया गया। डिजिटल लाइब्रेरी जिसमें वर्ष 2021 में लगभग 92 लाख सदस्य और 20 लाख ई-पुस्तकें थीं, का विस्तार तेजी से हो रहा है। शिक्षा फाउंडेशन ने आरडीपीआर विभाग के साथ सहयोग किया है और अपने "डिजिटल समावेशन कार्यक्रम" के तहत "ग्राम डिजी विकास" शुरू किया है, जिसमें राज्य की 1200 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। ग्राम पंचायत पुस्तकालय चार एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइस, एक एंड्रॉइड टीवी और इंटरनेट कनेक्शन / वाई-फाई हॉटस्पॉट, वार्षिक डेटा प्लान से लैस हैं।

(v) **संपर्क फाउंडेशन की पहल:** संपर्क फाउंडेशन के संस्थापक श्री विनीत नायर द्वारा बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार की दिशा में संपर्क फाउंडेशन की पहल पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। ग्रामीण स्कूली शिक्षा प्रणाली में नवाचार डिजिटल तकनीकों को अपनाकर इन सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संपर्क फाउंडेशन ने कई अभिनव समाधान विकसित किए हैं जैसे कि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक किट, पहेली बोर्ड, चैटबॉट, गेमीफाइड आकलन आदि। इस प्रकार, संपर्क फाउंडेशन इमर्सिव लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है, जिसका ग्रामीण बच्चों के सीखने के परिणामों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। संपर्क फाउंडेशन ने संपर्क टीवी सेटअप भी विकसित किया है, जो एक मानक टीवी को एक स्मार्ट टीवी में बदल देता है जो सीखने के मॉड्यूल के साथ पहले से लोड होता है। संपर्क फाउंडेशन 8 राज्यों में 1,00,000 से अधिक स्कूलों में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए स्कूलों को डिजिटल तकनीकों के साथ मुफ्त में सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

(vi) **स्मार्ट पंचायत पहल - उत्तर प्रदेश:** श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी, जिसमें ग्राम पंचायतों में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे के विकास सहित 4 प्रमुख पहलुओं जैसे प्रभावी सेवा वितरण और आय सृजन; पारदर्शी पंचायत कामकाज और हाई-स्पीड इंटरनेट - मुफ्त वाई-फाई का उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के एक अनूठे प्रयास में, बैंकिंग संवाददाता सखी (बीसी सखी) को क्रियाशील बनाया गया है, जिन्होंने 2200 करोड़ रुपये के लेनदेन की सुविधा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश राज्य ने स्थानीय शिक्षित युवाओं को 'ग्राम सहायक' के रूप में भर्ती करके, ग्राम पंचायत स्तर पर आईसीटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन दृष्टिकोण लाने की दिशा में एक नई पहल की है, जो न केवल मूल्य सृजन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तर के उद्यमियों के रूप में कार्य करेंगे बल्कि कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के साथ पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवा वितरण की सुविधा भी प्रदान करेंगे। इसके अलावा, राज्य ने सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में प्रत्येक जीपी के नागरिकों को मुफ्त वाई-फाई प्रदान करने की परिकल्पना की है। भविष्य में, राज्य पंचायत सचिवालयों में कुशल टेलीमेडिसिन और एडटेक सेवाओं सहित सेवा वितरण को मजबूत करने पर भी जोर देगा।

(vii) सीएससी एसपीवी की डिजी गांव पहल: सीएससी एसपीवी के मुख्य संचालन अधिकारी श्री ऋषिकेश पाटनकर ने स्मार्ट पंचायतों की दिशा में सीएससी की डिजी गांव पहल पर एक प्रस्तुति दी। अपनी प्रस्तुति देते हुए, श्री पाटनकर ने सीएससी द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य पहलों पर प्रकाश डाला, जैसे कि एमईआईटीवाई का प्रधान मंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, कानून और न्याय मंत्रालय की टेली लॉ पहल और संस्कृति मंत्रालय का संस्कृति सर्वेक्षण। एमईआईटीवाई की डिजी गांव पहल का उद्देश्य व्यापक विकास के लिए उपयुक्त ढांचा सुनिश्चित करके "डिजिटल डिवाइड" को कम करने के लिए डिजिटल रूप से कनेक्ट करना और लाभ/सेवाएं प्रदान करना है। यह परियोजना मार्च, 2023 तक देश भर के 700 गांवों, प्रति राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में प्रति गांव में लागू की जाएगी। डिलिवरेबल्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और बुनियादी ढांचे और सेवाओं के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें टेलीमेडिसिन, प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना आदि जैसी कई सेवाएं शामिल हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एर्गो, पेपाल, एचपी, एनईसी, यूको बैंक जैसे विभिन्न संगठनों से सीएसआर सहायता के माध्यम से लगभग 5000+ गांवों को डिजिटल ग्राम योजना के तहत कवर किया गया है। डिजिटल ग्राम योजना और सीएसआर प्रयासों के तहत कुल 10 मिलियन लाभार्थी शामिल हैं। डिजी गांव पहल ने लोगों को बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, उन्नत कंप्यूटर कौशल, खातों की मूल बातें समझने में सक्षम बनाया है और टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से बुनियादी निवारक स्वास्थ्य परामर्श भी प्रदान किया है। इस पहल ने एक वित्तीय रूप से समावेशी समाज का निर्माण करते हुए बैंकिंग, बीमा, डिजिटल भुगतान, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं के लिए अपनाने और ग्रहणशीलता की दर में भी सुधार किया है।

(viii) श्री विक्रम तेवतिया, डीडीजी, सीओएआई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल नेटवर्क कवरेज बढ़ाना: शुरुआत में श्री विक्रम तेवतिया ने ग्रामीण आईसीटी कनेक्टिविटी और नेटवर्क की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया। श्री तेवतिया ने तब दूरस्थ और कम सेवा वाले समुदायों में एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन के लिए एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के रूप में एक स्मार्ट गांव की व्यापक रूपरेखा रखी, जहां ग्रामीण निवासियों के पास जुड़े उपकरणों के माध्यम से नेटवर्क बुनियादी ढांचे तक पहुंच है और नागरिक प्रभावशाली और परिवर्तनकारी एसडीजी तक संबंधित डिजिटल सेवाएं, जैसा कि उन्हें उनकी आवश्यकता है, समय पर, कहीं भी और हर समय पहुंच सकते हैं। श्री तेवतिया ने विश्वसनीय ग्रामीण संपर्क सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल टावरों की आवश्यकता पर भी जोर दिया, क्योंकि अगले कुछ वर्षों में लगभग 25 लाख मोबाइल टावरों की आवश्यकता होगी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तारग संचार जैसे उपकरण ग्राम पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए, राज्य प्राधिकरण को राजपत्र आरओडब्ल्यू नियम 2016 को अपनाना

और लागू करना है। मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए ग्राम पंचायत भूमि और भवनों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ix) **स्मार्ट ग्राम पंचायतों के विकास का वित्तपोषण:** श्री एस के डोरा, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने स्मार्ट ग्राम पंचायतों के विकास के वित्तपोषण में नाबार्ड की भूमिका पर एक प्रस्तुति दी. प्रस्तुति के दौरान, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि नाबार्ड की पहल का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लगभग हर पहलू को छूने की दिशा में विशिष्ट लक्ष्य उन्मुख रणनीतियों के माध्यम से एक सशक्त और वित्तीय रूप से समावेशी ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। नाबार्ड अपनी वित्तीय और अनुदान सहायता के माध्यम से स्मार्ट ग्राम पंचायतों के विकास की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। पंचायती राज संस्थान नाबार्ड से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। नाबार्ड आरआईडीएफ के तहत मृदा संरक्षण और बाढ़ सुरक्षा, वाटरशेड विकास / जलभराव वाले क्षेत्रों, जल निकासी; वन विकास; सोलर पैनल आदि के सुधार के लिए भी सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड स्मार्ट औद्योगीकरण के लिए अनुदान सहायता प्रदान कर सकता है, नाबार्ड की विपणन पहल (ग्रामीण हाट, ग्रामीण मार्ट और ग्रामीण युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी पहल- अनुदान सहायता) के लिए सहायता प्रदान करता है। आगे जाकर, समृद्धि हासिल करने के लिए नाबार्ड सहभागी वित्तीय और गैर-वित्तीय हस्तक्षेपों, नवाचारों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से सतत और न्यायसंगत कृषि और ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थानों को बढ़ावा देने में सुविधा प्रदान करेगा।

(x) **श्री के सी झा, सलाहकार, जीईएम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता:** अपनी प्रस्तुति के दौरान, श्री के सी झा, सलाहकार, **जीईएम** ने इस बात पर प्रकाश डाला कि GeM, वन स्टॉप गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का एक संक्षिप्त रूप है जहाँ आम उपयोगकर्ता वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जा सकती है। **जीईएम** सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद करने के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है। **जीईएम** पूरी तरह से पेपरलेस, कैशलेस और सिस्टम संचालित ई-मार्केट प्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है। **जीईएम** विक्रेता पंजीकरण, ऑर्डर प्लेसमेंट और भुगतान प्रसंस्करण में मानव इंटरफ़ेस को काफी हद तक समाप्त कर देता है। एक खुला मंच होने के नाते, **जीईएम** सरकार के साथ व्यापार करने की इच्छा रखने वाले वास्तविक आपूर्तिकर्ताओं के लिए कोई प्रवेश बाधा नहीं है। हाल ही में, जीईएम को पंचायती राज मंत्रालय के ई-ग्रामस्वराज पीएफ़एमएस भुगतान इंटरफ़ेस के साथ एकीकृत किया गया है, जो जमीनी स्तर पर सार्वजनिक खरीद की पारदर्शिता को और बढ़ावा देता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के अंतिम चरण में है, जिसे गुरुग्राम हरियाणा में सफल पायलट द्वारा संचालित किया गया था। यह प्रयास पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करेगा जैसा कि यह सुनिश्चित करता है, ऑर्डर बुकिंग में पंचायतों के लिए

उपयोग में आसानी; 15वें वित्त आयोग अनुदानों के तहत पंचायतों द्वारा खरीद में पारदर्शिता और यह स्थानीय विक्रेताओं (मालिकों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों आदि) को जीईएम पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

(xi) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के प्रधान महाप्रबंधक श्री अतुल शर्मा द्वारा स्मार्ट ग्राम पंचायतों में स्मार्ट कनेक्टिविटी की भूमिका: शुरुआत में श्री अतुल शर्मा प्रधान महाप्रबंधक ने संकेत दिया कि भारतनेट, राष्ट्रीय महत्व की दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण इंटरनेट परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनता और संस्थानों को वहनीय ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सुलभ उच्च स्केलेबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। स्मार्ट कनेक्टिविटी स्मार्ट ग्राम पंचायतों के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। भारतनेट परियोजना जमीनी स्तर पर ई-गवर्नेंस सेवाओं जैसे भूमि रिकॉर्ड, जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार-आधारित सेवाओं, नरेगा को बढ़ावा देगी। यह बड़े प्रभावी पंचायत प्रबंधन की सुविधा भी प्रदान करेगा: - ग्राम सभा की बैठकें, ग्राम अभिलेखों का अद्यतन, नागरिक डेटाबेस और पंचायतों के प्रभावी प्रदर्शन की निगरानी। सामुदायिक भागीदारी: - अंतर-ग्राम, प्रथाओं और संसाधनों का अंतर-जिला साझाकरण। ब्लॉक व जिला आदि से संपर्क।

(xii) श्री प्रणय पाठक, रिलायंस जियो द्वारा कुशल ग्रामीण शासन और आर्थिक विकास के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी: श्री प्रणय पठान, रिलायंस जियो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रिलायंस जियो पूरे देश में दूरसंचार और कनेक्टिविटी में अग्रणी रहा है। आम तौर पर, हाई स्पीड इंटरनेट या तो फाइबर कनेक्टिविटी के माध्यम से या हाई स्पीड यूबीआर लिंक के माध्यम से प्रदान किया जाता है। वर्तमान में, वाई-फाई को ग्राम/ग्राम पंचायत में विद्यालय, डाकघर, सामुदायिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाडी केन्द्र, शासकीय राशन केन्द्र, पुलिस थाना, गृह आदि में ग्राम पंचायत/ग्राम से जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। जियो ने यूपी के 132 प्रमुख जनसंख्या केंद्रों में इंट्रासिटी ओएफसी नेटवर्क शुरू किया है और सभी डीएचक्यू/तहसीलों में एफटीटीएच नेटवर्क लागू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, 99.3% गाँव जिओ आरएफ़ कवरेज से आच्छादित हैं और 99.7% गाँव एमडबल्यू से 5 किमी के भीतर हैं। यह हाई स्पीड यूबीआर कनेक्टिविटी का उपयोग करके पूरे गांवों को वाईफाई कनेक्टिविटी पर कवर करने में सक्षम बनाता है। आगे बढ़ते हुए, विभिन्न स्मार्ट ग्रामीण समाधान जिनमें स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, स्मार्ट जेनसेट मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट फ्लीट मैनेजमेंट, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग सिस्टम और स्मार्ट कनेक्टेड कूलर शामिल हैं।

(xiii) डॉ. कृष्णा सिरोही, प्रो. ऑफ प्रैक्टिस, आईआईटी दिल्ली द्वारा ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए प्रौद्योगिकी विकल्प: अपनी प्रस्तुति के दौरान, प्रो. कृष्णा सिरोही, आईआईटी दिल्ली ने संकेत दिया कि देश के संपूर्ण आईसीटी और नेटवर्क पारिस्थितिकी तंत्र का गहन मूल्यांकन करने और ग्रामीण कनेक्टिविटी के

लिए समर्पित समाधान विकसित करने की योजना स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, किसान की आय में सुधार और खाद्य उत्पादन और आपूर्ति में भरोसा पैदा करने हेतु प्रौद्योगिकी समाधान स्थापित करने के लिए कृषि में उच्च अंत अनुसंधान पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, स्मार्ट विलेज कनेक्टिविटी सार्वजनिक दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवा प्रदाता बुनियादी ढांचे पर निर्भर है जो ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से अस्थिर है जिसके परिणामस्वरूप संचालन की उच्च लागत और सेवा की खराब गुणवत्ता होती है। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सेवा प्रदाता के प्रयासों को पूरा करने और स्थायी संपर्क अवसंरचना के विकास के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी परिनियोजन विकल्पों का पता लगाने की तत्काल आवश्यकता है। इस प्रकार, प्रत्येक गांव को अपने स्वयं के 5 जी निजी नेटवर्क की अनुमति देने के प्रावधानों का पता लगाने की आवश्यकता है और ग्राम पंचायतों को अपना नेटवर्क स्थापित करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन को भी प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। श्री अमरजीत सिन्हा ने सत्र को सारांशित करते हुए ग्राम पंचायतों, राज्य और जिला पंचायती राज अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योगों की ओर से सामुदायिक भागीदारी और सक्रिय प्रयास पर जोर दिया ताकि डिजिटल तकनीकों को अपनाकर ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए परियोजनाएं शुरू की जा सकें। सत्र के दौरान चर्चा किए गए हस्तक्षेप/कार्यों और सर्वोत्तम पद्धतियां न केवल प्रतिकृति के लिए मॉडल के रूप में काम करते हैं बल्कि ग्राम पंचायतों के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान का अवसर भी प्रदान करते हैं। श्री सिन्हा ने यह भी कहा कि अगले वर्ष सभी ग्राम पंचायतों को यहां चर्चा की गई स्मार्ट पंचायतों के तत्वों को अपनी ग्राम पंचायतों में लाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

ग. सत्र II- कुशल आईसीटी जनशक्ति

सत्र का संचालन श्री मदन पदाकी, सीईओ और संस्थापक, 1ब्रिज ने किया। श्री. पदाकी ने युवाओं और उद्यमिता, आर्थिक विकास में उनके योगदान और शासन के तीसरे स्तर में रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर देकर सत्र की शुरुआत की।

i. **सुश्री दिव्या खट्टर द्वारा उन्नत भारत अभियान की पहल, उन्नत भारत अभियान (यूबीए):** सुश्री दिव्या खट्टर ने संकेत दिया कि यूबीए को 2014 में शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। यह एक अनूठा कार्यक्रम है जो ग्रामीण भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, बाद में गांवों के विकास में योगदान देता है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा समन्वित किया जाता है। यूबीए की एक प्रमुख पहल में उच्च शिक्षा संस्थानों और गांवों के बीच एक क्रॉस लर्निंग प्लेटफॉर्म की स्थापना शामिल है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र और संकाय सदस्य पंचायत के लिए शिक्षा प्रणाली को कैलिब्रेट करने का एक तंत्र बनाने के लिए गांव के आवासों से जुड़ते हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान, शैक्षणिक संस्थान शिक्षा को लागू करने की योजना बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, एसएचजी के साथ सहयोग करते हैं। यूबीए के पास इस कार्यक्रम से जुड़े 3000 से अधिक संस्थान हैं जो जल शक्ति विभाग, ग्रामीण विकास विभाग आदि के साथ काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को करीब 55,000 शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ना है। एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्नत भारत अभियान और पंचायती राज मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

ii. **श्री वामसी उदयगिरी, सीईओ, हेसा ग्लोबल द्वारा ग्रामीण भारत को अपस्किलिंग:** श्री वामसी उदयगिरि ने कहा कि हेसा ग्लोबल एक बी2बी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हेसाथी नामक एक बड़ी जमीनी ताकत और शक्ति द्वारा समर्थित है, यह शक्तिशाली संयोजन व्यवसायों को ग्रामीण बाजार तक पहुंचने और एकीकृत करने की अनुमति देता है। युवाओं का प्रशिक्षण, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना - एचईएसए ग्लोबल

का उद्देश्य है और गांवों के लिए एक 'सुपरएप' बनाया गया है, जिसका उपयोग महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं द्वारा अपने लिए आजीविका सृजित करके किया जा रहा है।

iii. **श्री सौरज्येंदु मेद्दा, सीईओ, डीलशेयर द्वारा ग्रामीण भारत को अपस्किलिंग**: डीलशेयर के सीईओ श्री सौरजेंदु मेद्दा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डीलशेयर आठ राज्यों (उत्तर प्रदेश सहित) में उपस्थिति के साथ ग्रामीण भारत के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यह मुख्य रूप से स्थानीय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित/तैयार करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम करता है जहां स्थानीय निर्माता अपने उत्पादों का प्रदर्शन / बिक्री कर सकते हैं। ईकामर्स मूल्य निर्धारण, आपूर्ति श्रृंखला की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करता है। डीलशेयर ने अपने हस्तक्षेप के लिए एक निजी सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) मॉडल अपनाया। डीलशेयर के पास आपूर्ति श्रृंखला का अपना सीधा नेटवर्क है, जो लागत का अनुकूलन करता है। एक अन्य कारक केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा सृजित बुनियादी ढांचे का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ने से पंचायतों की बाहरी बाजार तक पहुंच होगी।

iv. **सुश्री मनदीप कौर द्वारा सिम्बा क्वार्ट्ज- ग्रामीण उद्यमिता का तंगरा बिजनेस मॉडल:** सुश्री मनदीप टांगरा ने कहा कि सिम्बाक्वार्ट्ज जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उनके दृष्टिकोण और पहल के बारे में बताया। सिम्बाक्वार्ट्ज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ग्राफिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जनशक्ति बनाने पर केंद्रित है। वे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए शहरी से ग्रामीण की ओर रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देते हैं। उनके हस्तक्षेप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए पैकेज्ड और ब्रांडेड दूध के बजाय स्थानीय घरों से दूध खरीदना शामिल है। महिलाओं के बीच आय सृजन के लिए टागरा में उनके द्वारा पेइंग-गेस्ट की अवधारणा पेश की गई थी। कुछ स्कूलों में कंपनी द्वारा बच्चों को जूते बांटे गए। स्पीकर ने ग्रामीण उत्थान के लिए एक संरचित नीति की गैर-मौजूदगी जैसी कुछ चुनौतियों का भी सामना किया, इंटरनेट सेवाएं अभी भी बहुत महंगी हैं और ग्रामीण स्तर पर खराब नेटवर्क हैं।

सत्र का समापन करने के लिए श्री. मदन पददकी ने आकांक्षी युवाओं के महत्व के बारे में बताया, उनके आत्मविश्वास का निर्माण किया। उन्होंने कर्नाटक के कोटागुड्डा पंचायत के श्री रमेश के केस-स्टडी का भी प्रदर्शन किया, जिसमें एक गैर-अंग्रेजी भाषी युवा के अंग्रेजी में समृद्ध होने के लिए एक व्यापक परिवर्तन दिखाया गया था। श्री रमेश सीएनएन-आईबीएन रियल हीरोज अवार्ड जीतने के लिए आगे बढ़े क्योंकि वे एक सार्वजनिक वक्ता बन गए। इसी तरह का परिवर्तन गांवों के 25,000 युवाओं में देखा गया है। उन्होंने कुछ अनुकरणीय उदाहरणों का हवाला देते हुए हर गांव में उद्यमी पैदा करने पर जोर दिया।

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

घ. सत्र III- स्मार्ट ऊर्जा

सत्र का संचालन श्री अशोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया गया। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए श्री श्रीवास्तव ने जमीनी स्तर पर विकेन्द्रीकृत ऊर्जा समाधान की आवश्यकता और ग्राम पंचायतों के सक्रिय प्रयासों पर जोर दिया।

i. **सुश्री पवित्रा सिन्हा, शक्ति फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा को अपनाने में चुनौतियां:** सुश्री पवित्रा सिन्हा, शक्ति फाउंडेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा को अपनाने में चुनौतियों पर प्रकाश डाला। शक्ति फाउंडेशन नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में सहायता करके स्वच्छ ऊर्जा भविष्य में भारत के संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता, और सतत परिवहन प्रदान करना है और जलवायु गतिविधियों के क्रॉस-कटिंग स्पेस में, फाउंडेशन में एमएनआरई, नीति आयोग, एमओईएफसीसी, एनएचएसआरसी, गोटीएन, गोबी, आदि के साथ जुड़ाव और समझौता ज्ञापन भी हैं। शक्ति फाउंडेशन ने डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी (डीआरई) के माध्यम से आय के अवसरों को बढ़ाने, कठिन परिश्रम को कम करने, और वंचित समुदायों के लिए शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत में बिजली के अंतिम मील वितरण को मजबूत करने पर काम किया है। यह भी बताया गया कि डीआरई को बढ़ावा देने के लिए पांच फोकल क्षेत्र हैं, अर्थात् कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रूफ-टॉप सोलर और वित्त। वर्तमान परिदृश्य में, सौभाग्य योजना के तहत, 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल किया गया है और ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं। बिजली गुल होने की चुनौती अभी भी बनी हुई है।

यह सुझाव दिया गया था कि डीआरई मुद्दों को हल करने में मदद कर सकता है क्योंकि डीआरई का मतलब है जब बिजली संयंत्रों अक्सर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उपयोग के बिंदु के पास से केंद्रीकृत उत्पादन स्रोतों के बजाय स्रोतों से बिजली उत्पन्न होती है। डीआरई ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी उदाहरण कोल्ड स्टोरेज के साथ भी प्रतिस्पर्धी है। डीआरई मूल रूप से लागत प्रभावी टैरिफ, ऊर्जा सुरक्षा और सशक्त आजीविका प्रदान करते हैं। डीआरई प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए कई चुनौतियां हैं क्योंकि कई लाभार्थी/हितधारक मौजूद हैं। मुख्य रूप से 4 लाभार्थी हैं, अर्थात् डेवलपर्स, उपभोक्ता, कार्यान्वयन एजेंसियां और फाइनेंसर। यह भी बताया गया कि वितरित अक्षय ऊर्जा (डीआरई) में ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में ऊर्जा पहुंच चुनौतियों को हल करने की क्षमता है।

ii. **श्री जे के जेठानी, वैज्ञानिक, एमएनआरई द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार की पहल:** श्री जे के जेठानी ने अक्षय ऊर्जा बनाने के लिए गांवों के महत्व पर जोर दिया, जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्ष 2020-30 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने की कल्पना की गई थी और वर्तमान में हम 160 गीगावॉट तक खड़े हैं। ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाने के लिए गांवों को उन उपकरणों की पहचान करनी होगी जिनका उपयोग अक्षय ऊर्जा के साथ किया जा सकता है। श्री जेठानी ने ग्रामीण समुदायों के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने, ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ाने और शिक्षा और आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए एआरईएएस, एनआरडीसी, और एसईवीए द्वारा विकसित हरियाली ग्राम की अवधारणा के बारे में भी बताया। स्मार्ट ऊर्जा समाधान एलईडी बल्ब, सौर लैंप, ठंडी छतों का उपयोग, सौर पंपों का उन्नत उपयोग और सामुदायिक स्तर के हस्तक्षेप का व्यापक उपयोग हो सकता है। एमएनआरई ने 35 लाख किसानों के लिए कृषि पंपों के सौरकरण के लिए सहायता प्रदान करके पीएम-कुसुम योजना सहायता के तहत किसान, किसान/पंचायत की भूमि पर 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता, विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा (डीआरई) आजीविका अनुप्रयोग, आदि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहल की है। अध्यक्ष ने पीएम कुसुम योजना के घटकों के बारे में बताया, जिसमें घटक ए, एक बंजर भूमि में सौर संयंत्र स्थापित किया जा सकता है और संयंत्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को वितरण कंपनियों को बेचा जा सकता है। घटक बी में, डीजल पंपों को सौर पंपों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है और घटक सी में, जहां पंप पहले से बिजली के साथ काम कर रहा है, अक्षय ऊर्जा के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। स्पीकर द्वारा इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि जिन गांवों में छत पर सोलर पैनल लगाने की क्षमता नहीं है, वहां वर्चुअल नेट मीटरिंग की अवधारणा का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें सोलर प्लांट से उत्पादित बिजली को कई ग्राहकों के बिलों में आवंटित किया जाता है। ऊर्जा के उपरोक्त हाइलाइट किए गए स्रोतों के अलावा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मौजूद हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में मिनी, सूक्ष्म और लघु जलविद्युत

संयंत्र विद्युत / यांत्रिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं, प्रमुख कृषि राज्यों में बायोमास गैसीफायर और अन्य स्रोत विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं।

iii. **ओदंथुरई ग्राम पंचायत, तमिलनाडु द्वारा ओदंथुरई ग्राम पंचायत, तमिलनाडु के प्रतिनिधि द्वारा अनुभव साझा करना:** ओदंथुरई ग्राम पंचायत के सरपंच ने बताया कि पंचायत पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासी आबादी के साथ है और ज्यादातर कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। पंचायत के लिए राजस्व का अपना स्रोत पवन चक्कियों से उत्पन्न ऊर्जा है। इसका मूल्य 1.55 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2021-22 में इस पवनचक्की ने 4.60 लाख विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया। ग्राम पंचायत में केन्द्र स्तर की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजना ने पंचायत को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया है और अन्य योजनाओं को लागू करके, ग्राम पंचायत में बिजली और गुणवत्ता वाली सड़कें भी प्रदान की गई हैं।

iv. **श्री शिरीष गरुड़, अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, टेरी द्वारा कम लागत और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ऊर्जा समाधान:** श्री शिरीष गरुड़ ने बताया कि ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, टेरी की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी और तब से यह ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्रों की गतिविधियों में, संगठन सरकारी एजेंसियों जैसे GIVICA, बिहार और अन्य सरकारों के साथ काम कर रहा है और अन्य कॉर्पोरेट समूहों जैसे IKEA, Vodafone, आदि के साथ भी काम कर रहा है। टेरी ने स्वास्थ्य देखभाल में उपयोग के लिए सौर आधारित डीप फ्रीजर, सोलर प्लांट और स्ट्रीट लाइट, वाटर एटीएम जैसे संस्थानों में स्वच्छ पानी की सुविधा, सोलर माइक्रो इरिगेशन पंप सेट और आईडीईएस-एकीकृत घरेलू ऊर्जा प्रणाली जैसे विभिन्न कार्य शुरू किए हैं जो स्वच्छ खाना पकाने और प्रकाश समाधान प्रदान करते हैं जिससे इनडोर वायु प्रदूषण की अन्य प्रमुख समस्याओं का समाधान होता है। श्री गरुड़ ने पंचायती राज संस्थाओं से इन दृष्टिकोणों को ग्राम स्तर पर एकीकृत करने का आग्रह किया।

श्री अशोक श्रीवास्तव, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने संक्षेप में बताया कि अक्षय ऊर्जा ग्रामीण आबादी के सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार का अवसर प्रदान करती है। वितरित अक्षय ऊर्जा (डीआरई) समाधान जैसे ऑफ-ग्रिड सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) सिस्टम, सोलर लालटेन, सोलर स्टडी लैंप, सोलर माइक्रो और मिनी-ग्रिड, पवन ऊर्जा आदि, ग्रामीण आबादी की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पहला दिन निष्कर्ष- सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की टिप्पणी

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार ने प्रतिभागियों को बेहतर काम के अवसरों की तलाश में ग्रामीण भारत से शहरों में वयस्कों के अनुचित पलायन को रोकने के लिए, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र स्मार्ट पंचायत बनाने के महत्व से अवगत कराया। श्री कुमार ने यह भी उल्लेख किया कि ग्रामीण स्तर पर ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलीकरण (डिजिटल सेवा वितरण को बढ़ावा देना) और शिक्षित जनशक्ति, विकास की नींव रखती है। उत्तर प्रदेश में ग्राम स्तरीय उद्यमियों जैसे राज्य स्तरीय पहलों के उदाहरण और महाराष्ट्र, स्मार्ट विलेज - स्मार्ट आंध्र प्रदेश की ओर स्मार्ट वार्ड, कोयंबटूर में ओडनथुरई पंचायत की बिजली उत्पादन, और गुजरात के पुंसारी पंचायत में सीसीटीवी और बायो-मीट्रिक मशीनों की स्थापना, वातानुकूलित कक्षाओं, वाई-फाई कवरेज का हवाला दिया गया। ग्रामीण विकास को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रिया को क्रियान्वित करने और निगरानी करने के लिए एक रणनीति/मॉडल तैयार करना आवश्यक है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, विनियमों और प्रबंधन के आधार पर नागरिकों की भागीदारी के साथ क्लस्टर दृष्टिकोण, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित एक विशेष रूप से तैयार किया गया उपयुक्त ढांचा अगली पीढ़ी के स्मार्ट गांवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रामीण नीतियों को एकीकृत रणनीतियों और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान और गतिशीलता पर निर्माण करना चाहिए। उन्हें विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और उद्यमिता, निवेश, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। इन नीतियों को ग्रामीण पहचान को भी महत्व देना चाहिए और स्थिरता, सामाजिक समावेश और स्थानीय विकास के साथ-साथ ग्रामीण समुदायों के लचीलेपन को बढ़ाना चाहिए।

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

दूसरा दिन (16 सितंबर, 2022)

ङ. सत्र IV- स्मार्ट कृषि और स्मार्ट पर्यावरण

सत्र का संचालन श्री आलोक अग्रवाल, पार्टनर, डेलॉइट द्वारा किया गया। अपनी प्रारंभिक टिप्पणी करते हुए, श्री अग्रवाल ने कहा कि डिजिटल तकनीक किसानों को क्षेत्र में जानकारी एकत्र करने के लिए सशक्त बना सकती है और यह उम्मीद की जाती है कि वे भविष्य में भूमि के प्रत्येक भूखंड की निगरानी कर सकें ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्हें कम लागत के साथ खेती के लिए संसाधनों का उपयोग किस फसल का उत्पादन करने की आवश्यकता है।

i. **श्री अभय पारीक द्वारा कृषि में परिवर्तनकारी ड्रोन प्रौद्योगिकी, कृषि के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व, विश्व आर्थिक मंच:** श्री अभय पारीक ने एआई, आईओटी, ब्लॉकचैन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में बात की, ड्रोन कृषि क्षेत्र सहित हमारे आसपास की दुनिया को बदल रहे हैं। ये प्रौद्योगिकियां संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ उत्पादन में दक्षता पैदा कर सकती हैं और किसानों के लिए नए बाजार खोल सकती हैं। यह भी संकेत दिया गया था कि स्मार्ट ग्राम पंचायत में समुदायों का लक्ष्य संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के साथ-साथ किसानों के लिए उत्पादकता और आय बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ-साथ लचीलापन बढ़ाने और स्थानीय ताकत पर निर्माण करने के लिए कृषि प्रथाओं को बदलना होगा। श्री पारीक ने संकेत दिया कि विभिन्न तकनीकों के हस्तक्षेप से सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4 लाख करोड़ की वृद्धि की जा सकती है और किसान अधिकतम उत्पादन के लिए कृषि प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए नवीनतम रुझानों से अवगत हो जाते हैं। खेती के लिए ड्रोन इनपुट लागत को 25% तक कम कर सकता है और यह किसानों के स्वास्थ्य को 90% तक बचा सकता है। प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के साथ, किसान सटीक और जलवायु स्मार्ट कृषि प्रथाओं, बीमा और सामाजिक सुरक्षा को अपनाने के लिए ऋण तक पहुंच बढ़ा सकते हैं ताकि घाटे के प्रति लचीलापन बढ़ाया जा सके; सलाह के माध्यम से कृषि उत्पादन में दक्षता में वृद्धि, आवश्यक इनपुट तक पहुंच और इनपुट के कुशल उपयोग के लिए प्रथाओं के पैकेज का सुझाव दिया गया और

उपज के लिए ईष्टतम रिटर्न प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मध्यस्थता के साथ छोटे धारक और एफपीओ की बाजारों तक पहुंच को बढ़ाया गया। यह आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और अधिक प्रभावी होगा। जो स्थानीय संसाधनों की क्षमता और आजीविका के अवसर बनाने में मदद करता है। श्री पारीक ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में आयोजित राज्य स्तरीय पायलट कार्यक्रम सहित डब्ल्यूईएफ द्वारा किए गए कार्यों पर भी प्रकाश डाला।

ii. **श्री देबाशीष विश्वास द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन, पार्टनर, डेलॉइट:** श्री देबाशीष विश्वास ने पराली जलाने के विभिन्न विकल्पों और कृषि अपशिष्ट प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा की। प्रस्तुति का संदर्भ देते हुए श्री विश्वास ने बताया कि हरियाणा में केवल वर्ष 2021 में 7000 से अधिक आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, फसलों के जलने के कारण ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन होता है और पोषक तत्वों की हानि मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती है। रिकॉर्ड के अनुसार, हरियाणा में 1.6 मीट्रिक टन पराली जला दी गई, जिससे कृषि आय और कृषि आय और कृषि उपज कम हो जाती है। श्री विश्वास ने यह भी बताया कि निसिंग और करनाल ब्लॉक के 1500 किसानों के लिए ऐप-इंटरफ़ेस का उपयोग करके एक व्यक्तिगत सर्वेक्षण किया गया था। राज्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, कृषि अधिकारियों, सीएचसी, केवीके, स्टार्ट-अप सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विभिन्न बैठकें/बातचीत आयोजित की गई। उन्होंने प्रस्तावित हस्तक्षेप/कार्य भी प्रस्तुत किया। पराली जलाने से निपटने के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण पर चर्चा की गई। फसल अवशेष प्रबंधन समाधानों का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक पराली प्रबंधन योजना प्रस्तुत की गई थी जो किसानों को प्रोत्साहित करती है और पराली जलाने को सीमित करती है।

iii. **श्री अर्जुन वेंकटरमण द्वारा स्मार्ट कृषि अवसर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन:** शुरुआत में, श्री अर्जुन वेंकरमण ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और परिवर्तन के 5 चरणों की मदद से समावेशी कृषि परिवर्तन (आईएटी) की व्याख्या की। इसके अलावा, आईएटी छोटे धारक क्षेत्र में उत्पादकता-आधारित विकास है जो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं के पक्ष में व्यापक और त्वरित प्रभाव डालता है। आईएटी के पांच चरणों में निर्वाह कृषि शामिल है; कृषि को आगे बढ़ाना; विकास में योगदानकर्ता के रूप में कृषि; कृषि को समष्टि-अर्थव्यवस्था में और कृषि को औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में एकीकृत करना। श्री वेंकटरमन ने

यह भी संकेत दिया कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चार रणनीतिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि परिवर्तन समावेशी है, अर्थात्, एसएचएफ के लिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि, एसएचएफ परिवारों की आय में वृद्धि; साल भर सुरक्षित, किफायती, पौष्टिक आहार का समान उपभोग बढ़ाना और कृषि में महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना। सरकार, शिक्षा, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रों के विविध संगठनों में अनुदान पाने वालों के एक बड़े समूह द्वारा काम संभव बनाया गया है। श्री वेंकटरमण ने फाउंडेशन द्वारा आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी।

iv. **श्री मिन्हाज आलम, अपर सचिव, ओडीओपी द्वारा भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रभाव:** एमओएफपीआई के अपर सचिव श्री मिन्हाज आलम ने "भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रभाव" पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। श्री आलम ने बताया कि ओडीओपी पहले उत्तर प्रदेश में बनाया गया था और तब से इसे कृषि, वाणिज्य, खाद्य प्रसंस्करण और कपड़ा जैसे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनाया गया है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना का पीएम औपचारिकीकरण 20 मई, 2020 को वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि में लागू किए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। योजना में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड अनुदान की परिकल्पना की गई है। फिर योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं पर भी चर्चा की गई। श्री आलम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने के लाभों को प्राप्त करने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए चार अंतर्निहित कदमों में शामिल हैं, व्यक्तिगत और समूह इकाइयों को सहायता; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; विपणन और ब्रांडिंग और औपचारिकता के लिए समर्थन। श्री आलम ने यह भी बताया कि ओडीओपी के रूप में पहचान की गई 16 उत्पाद श्रेणियों में 137 अद्वितीय उत्पादों के साथ 25 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के 713 जिलों के लिए ओडीओपी को मंजूरी दी गई है। फिर उन्होंने ओडीओपी योजना की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, ओडीओपी का उद्देश्य आर्थिक विकास, निवेश में वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन और क्षेत्र के रोजगार सृजन के साथ-साथ कौशल, कार्यबल के पुन: कौशल, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और सभी को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना और क्षेत्र के रोजगार सृजन को प्राप्त करना है। आय असमानता, ग्रामीण-शहरी प्रवास के बढ़ते दबाव, स्थानीय कौशल और शिल्प के लुप्त होने और रोजगार के अवसरों की कमी की समस्या का सामना कर रहे उन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक पुनरोद्धार और समावेशी विकास के लिए इसका अत्यधिक लाभ है।

v. **भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में डॉ. केतकी बापट द्वारा ग्रामीण बाज़ार:** डॉ. केतकी बापट ने रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (आरयूटीएजी) द्वारा विकसित ग्रामीण प्रौद्योगिकी समाधानों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। डॉ. बापट ने बताया कि पीएसए के कार्यालय ने वर्ष 2003 में

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह (आरयूटीएजी) कार्यक्रम की अवधारणा की थी जो आवश्यक तालमेल के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए एक तंत्र प्रदान कर सकता है। RuTAG विभिन्न व्यावसायिक समूहों को समाधान देने के उद्देश्य से एक तालमेल और उत्प्रेरित तंत्र है, उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए कठिन परिश्रम को कम करना है। इसे सात IIT की मदद से विकसित/तैयार किया गया था। आरयूटीएजी केंद्र मांग-संचालित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी अंतराल को पाटने में मदद कर रहे हैं, प्रशिक्षण और तकनीकी हैंडहोल्डिंग पकड़ रहे हैं। RuTAG एक तालमेल और उत्प्रेरित तंत्र है जिसका उद्देश्य विभिन्न व्यावसायिक समूहों को समाधान प्रदान करना, कठिन परिश्रम को कम करना और नवीन दृष्टिकोण के साथ प्रौद्योगिकी अंतराल को पाटना और प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करना एवं उनके उत्पादों और सेवाओं में मूल्यवर्धक बनाना है। डॉ. बापट ने तब पंचायती राज मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से पीएसए कार्यालय की ई-वेंडिंग कार्ट पहल का प्रदर्शन किया, जिसमें सब्जी कूलर, वेंडिंग कार्ट एक्सेसरीज, थेला सम्राट, स्मार्ट वेंडिंग कार्ड, सब्जी वेंडिंग कार्ड आदि एयर कूल्ड आधारित मॉडल शामिल हैं।

vi. **श्री शिरीष जोशी, मुख्य व्यवसाय अधिकारी, ओएनडीसी द्वारा ग्रामीण ई-कॉमर्स में अवसर:** श्री शिरीष जोशी ने ग्रामीण ई-कॉमर्स में अवसर और ग्रामीण ई-कॉमर्स में सुधार के लिए ओएनडीसी के प्रयासों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। श्री जोशी ने संकेत दिया कि ओएनडीसी का लक्ष्य नाटकीय रूप से ईकामर्स पैठ को बढ़ाना है - जनसंख्या पैमाने पर समावेशन । श्री जोशी ने यह भी बताया कि ओएनडीसी को मूल्य श्रृंखला में प्रमुख कारकों को हल करने और ग्रामीण ई-कॉमर्स में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जैसे कि विक्रेताओं के ऑनलाइन होने के लिए सीमित विकल्प, खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए अपने स्वयं के नियम और शर्तों को निर्धारित करने में असमर्थता आदि। इसके अलावा, उन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने के लिए ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के लाभों के बारे में बताया। श्री जोशी ने ओएनडीसी को ई-कॉमर्स का यूपीआई भी कहा जिसमें ग्राहकों द्वारा ई-कॉमर्स गतिविधि के लिए विभिन्न ई-कॉमर्स वेबसाइटों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। यह सूचित किया गया कि ओएनडीसी का डिजाइन 2 परस्पर संबंधित सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमता है जिसमें बाजार में जाने के प्रयासों को कम करने के लिए ग्राहक और विक्रेता अधिग्रहण को

अलग करना और अधिक बाजार पहुंच के लिए प्लेटफार्मों / एप्लीकेशन के बीच अंतर-संचालनीयता शामिल है।

vii. **ई-चौपाल मॉडल-** श्री कुमार प्रणेश, क्षेत्रीय प्रमुख, आईटीसी द्वारा भारतीय कृषि व्यवसाय क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: शुरुआत में, श्री कुमार प्रणेश ने दर्शकों को बताया कि ई-चौपाल मॉडल 160+ स्थान और 6000+ ई-चौपाल और संचालकों सहित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 220 जिलों में मौजूद है। अब तक, 4 मिलियन से अधिक किसानों को जोड़ा गया है और 3 लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि फसल विकास कार्यक्रमों के तहत कवर की गई है। उन्होंने ई-चौपालों के बुनियादी कार्यों का भी वर्णन किया। इसके बाद श्री प्रणेश ने चौपाल सागर, ईंधन स्टेशन, चौपाल हाट आदि ई-चौपाल के तहत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर प्रकाश डाला और किसानों को मोबाइल के माध्यम से विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने के लिए आईटीसी मार्स ऐप की विभिन्न विशेषताओं को प्रस्तुत किया। श्री प्रणेश ने किसानों की जरूरतों के लिए विभिन्न प्रकार के ऋण विकल्पों का लाभ उठाने के लिए आईटीसी मार्स के सहज अनुभव और किसानों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में इसके विकास से भी अवगत कराया। अंत में, श्री प्रणेश ने कृषि-व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए समाधान प्रस्तावित किए, जिसमें शामिल हैं, समूहों में परिमाण की मितव्ययता और बाजार से जुड़े फसल उत्पादन का लाभ उठाना; कृषि आदानों की सामूहिक सोर्सिंग; औपचारिक क्रेडिट लिंकेज बढ़ाने की संभावना; सामूहिकता के कारण लागत दक्षता के साथ बाजार पहुंच में वृद्धि; मांग एकत्रीकरण और पूर्ति - प्रत्येक स्तर तक परिमाण की मितव्ययता।

viii. **सुश्री मनीषा चौधरी, राष्ट्रीय समन्वयक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्यावरणीय सर्वोत्तम अभ्यास:** सुश्री मनीषा चौधरी ने पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (इको-डीआरआर) के बारे में जानकारी दी और कहा कि पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण - जैसे कि वन, आर्द्रभूमि, तटीय और समुद्री प्रणाली, और शुष्क भूमि - आपदा जोखिम का एक प्रमुख चालक है और आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता का एक प्रमुख घटक है। इसके अलावा, इको-डीआरआर उपायों की पहचान लागत प्रभावी और टिकाऊ उपायों के रूप में की जाती है, जो भूस्खलन, बाढ़, सूखा, तटीय खतरों और जमीन विशेष रूप से कमजोर आबादी पर जंगल की आग सहित विभिन्न खतरों के प्रभाव को कम करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, अंजुथेंगु ग्राम पंचायत पर एक केस स्टडी भी प्रस्तुत की गई जिसमें मैंग्रोव और अन्य प्रजातियों का उपयोग करके तटीय वनीकरण कार्य के बारे में कदम शामिल थे; महात्मा गांधी नरेगा निधि का उपयोग स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है और इन कदमों के प्रभाव जैसे कि अधिक स्थिर तट और कम कटाव। सुश्री चौधरी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पिछले 100 वर्षों में, 90 प्रतिशत से अधिक फसल किस्में गायब हो गई हैं और आज, कुल फसल उत्पादन में केवल नौ पौधों की प्रजातियां 66 प्रतिशत का योगदान करती हैं - जो मधुमेह, मोटापा और कुपोषण जैसे सर्वव्यापी स्वास्थ्य जोखिमों में योगदान करती हैं। इसके अलावा, कपड़ा क्षेत्र दुनिया के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 8 प्रतिशत

हिस्सा है। कपड़ा रंगाई विश्व स्तर पर पानी का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है। सुश्री चौधरी ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं - पंचामृत; लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली); सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध; 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि की बहाली; एसडीजी के लिए जैव विविधता संरक्षण और लक्ष्य के बारे में बताया।

ix. **मीनांगडी पंचायत, केरल- श्री के ई विनयन, अध्यक्ष, मीनांगडी ग्राम पंचायत द्वारा कार्बन तटस्थता की ओर:** ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ने अपनी पंचायत को कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। पंचायत को देश में पहली कार्बन-न्यूट्रल पंचायत बनाने के लिए कई पहल की गईं। ओदंथुराई ग्राम पंचायत के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि वृक्ष बंधक योजना को अपनाकर वृक्ष बैंकिंग योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए। यह परियोजना 6 साल पहले शुरू की गई थी और कार्बन न्यूट्रल मीनांगडी की परियोजना को पूरा करने में 3 साल और लगेंगे। 'कार्बन तटस्थता' की अवधारणा शून्य-कार्बन विकास, प्रकृति संरक्षण, खाद्य-ऊर्जा आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास की धारणाओं को सामने रखती है। चूंकि मानवीय गतिविधियां वर्तमान जलवायु संकट का मुख्य कारण हैं, इसलिए हमारे ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करना और बढ़ते विषम मौसम की घटनाओं के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। शून्य-कार्बन विकास जो स्थायी जीवन को बढ़ावा देता है, मानवजनित उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ हमारे लचीलेपन में सुधार करने का एक प्रभावी समाधान है। इसके अलावा, पंचायत से प्राथमिक और साथ ही माध्यमिक डेटा का उपयोग करके राष्ट्रीय जीएचजी सूची (2006) के लिए आईपीसीसी दिशानिर्देशों के आधार पर उत्सर्जन और पृथक्करण विश्लेषण किया गया था। यूएनईपी के लो कार्बन मोबिलिटी टूलकिट का उपयोग परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन के आकलन के लिए किया गया था।

च. सत्र V - स्मार्ट स्वास्थ्य

स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन के दूसरे दिन स्मार्ट स्वास्थ्य की थीम पर दूसरा सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र का संचालन श्री (डॉ.) इंदु भूषण, पूर्व सीईओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया। सत्र

का सञ्चालन करते हुए, श्री (डॉ.) भूषण ने दर्शकों को ग्रामीण और शहरी भारत के बीच विभाजन पर जोर देते हुए संबोधित किया। श्री (डॉ.) भूषण ने इस बात पर प्रकाश डालने के लिए प्रमुख डेटा बिंदु प्रस्तुत किए कि ग्रामीण भारत अपने शहरी समकक्ष से शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), स्टेंटिंग, स्वास्थ्य सुविधा से दूरी, स्वास्थ्य प्रदाताओं की उपलब्धता और एड्स/ एचआईवी के बारे में महिलाओं के बीच ज्ञान जैसे क्षेत्रों में पिछड़ गया है। तथापि, यह प्रशंसनीय था कि टीकाकरण में ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। श्री (डॉ.) भूषण ने उन क्षेत्रों पर अपने विचार साझा किए जहां डिजिटल और संचार प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों की मदद कर सकती है जैसे नई प्रौद्योगिकियों और उपचारों तक पहुंच में तेजी लाना; चिकित्सा देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में सुधार; मौजूदा स्वास्थ्य कार्यक्रम का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन; देखभाल की निरंतरता को मजबूत करना और विभिन्न विभागों के कामकाज का बेहतर समन्वय करना।

i. **ग्रामीण स्वास्थ्य तैयारी और बुनियादी ढांचे का विकास श्री श्यामल संतरा, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया (टीआरआई) फाउंडेशन द्वारा:** श्री संतरा ने ग्रामीण भारत में हेल्थकेयर के भविष्य की पुनर्कल्पना पर अपना विजन साझा किया। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण में देरी के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं शामिल हैं, जो देखभाल की मांग के निर्णय में देरी का कारण बनती हैं; स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान और उपलब्धता में देरी और देखभाल की गुणवत्ता, जिसके कारण पर्याप्त और उचित उपचार की प्राप्ति में देरी के साथ-साथ देखभाल की मांग के निर्णय में देरी होती है। एक शिशु के जीवन के पहले 1,000 दिनों में, नौ क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार के लिए जोर दिया जाना चाहिए। समुदायों की सामाजिक पूंजी और डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा प्रवर्तित एसएचजी-वीओ-सीएलएफ प्लेटफॉर्म को मांग सृजन, अधिकारों तक पहुंच और सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए समर्थन की भी आवश्यकता है। सेवाओं और सामुदायिक प्रतिक्रिया तंत्र के साथ ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति को मजबूत करना, साथ ही स्वास्थ्य स्टार्टअप को शामिल करते हुए सेवा वितरण के अभिनव तरीके की खोज करना भी आवश्यक है। इसके अलावा, डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल, टेलीमेडिसिन, और रेफरल सुविधाओं के साथ एकीकृत स्वास्थ्य नेटवर्क की आवश्यकता होगी और

स्वास्थ्य कार्यबल अंतराल को भरने, जिलों में कार्यबल आवंटन के युक्तिकरण और क्षमता निर्माण में सहायता की भी आवश्यकता होगी। टीआरआई विभिन्न चरणों में सरकार की कई योजनाओं और पहलों को लक्षित कर रहा है, जैसे गर्भ निरोधकों की होम डिलीवरी, बढ़ी हुई मुआवजा योजना; सुविधा और घर-आधारित नवजात शिशु देखभाल, एचबीवाईसी, टीकाकरण, स्तनपान, टीकाकरण और पोषण सुविधाओं को बढ़ावा देना। हाल के महामारी परिदृश्य ने सहयोगी स्वास्थ्य प्रबंधन का एक नया आयाम खोल दिया है, जिसमें समुदायों ने जीवन रक्षक व्यवहारों को अपनाने में नागरिकों की भागीदारी देखी है। पंचायती राज संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों और स्वास्थ्य प्रणालियां एनआरएलएम के तहत महिला समूहों का बड़े पैमाने पर लामबंदी; सीबीओ में महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से उत्पन्न सामाजिक पूंजी और व्यवहार, मानदंडों और आदतों से सीधे संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने के संभावित समाधान से प्रभावित होती हैं ।

ii. **श्री अमित सिंह, कार्यकारी निदेशक, डेलॉयट द्वारा आईटी और संबंधित तकनीकों का लाभ उठाने वाली सिटीजन सेंट्रिक हेल्थकेयर:** शुरुआत में, श्री अमित सिंह ने ग्रामीण स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जैसे अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, चिकित्सा कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच । इस संबंध में, ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए एक तीन स्तरीय स्मार्ट स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाया जा सकता है। स्मार्ट हेल्थ इकोसिस्टम में, टियर 1 - स्मार्ट केयर में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से प्रदाता के नेतृत्व में रखरखाव और बीमारी, बीमारी और चोट में सुधार शामिल होगा; टियर 2 - वर्चुअल केयर में स्व-प्रबंधित और प्रदाता के नेतृत्व वाली देखभाल के बीच क्रॉसओवर शामिल होगा और टियर 3 - स्मार्ट हेल्थ कम्युनिटीज में एक ऐसी इकाई शामिल होगी जो पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली से बाहर काम करती है और भौगोलिक या आभासी समुदाय सेटिंग में समग्र कल्याण के साथ रोग की रोकथाम को प्रोत्साहित करती है। ऐसी संस्थाएं एक समुदाय (जैसे, शिक्षा, भोजन, आवास, आदि) में स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने में मदद करने के लिए साक्ष्य-आधारित ध्यानाकर्षण के साथ प्रौद्योगिकी का तेजी से लाभ उठाती हैं। किसी विशेष ग्रामीण समुदाय में आईसीटी हस्तक्षेप की परिपक्वता अवस्था के आधार पर, अनुभवी चिकित्सकों के साथ घर पर सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त टेली-परामर्श; प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को घर से पीएचसी/सीएचसी/डायग्नोस्टिक लैब तक जारी रखना; आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस सेवा; एकीकृत निगरानी और डेटा संचालित निर्णय लेने आदि जैसे रास्ते तलाशे जा सकते हैं ।

इस सत्र का सार श्री (डॉ.) भूषण द्वारा किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि भारत में जीपी स्तर पर किए गए समान सक्षम पहलों को साझा करने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक केंद्रित सम्मेलन और/या कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए। स्मार्ट स्वास्थ्य क्षेत्र में श्री (डॉ.) भूषण ने स्वास्थ्य क्षेत्र के

यूपीआई के समान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का भी उल्लेख किया। एक बार लागू होने के बाद, प्रत्येक नागरिक, व्यवसायी और सुविधा, स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ, निर्बाध स्वास्थ्य सेवा वितरण की सुविधा के लिए एक अद्वितीय डिजिटल आईडी द्वारा नामित किया जाएगा। इस मिशन में प्रत्येक रोगी के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) का बनाया जाना भी शामिल होगा, जिसके द्वारा किसी भी समय, कहीं भी, रोगी की डिजिटल चिकित्सा जानकारी उपलब्ध रहेगी।

छ. सत्र VI- पूर्वोत्तर क्षेत्र उन्मुखी दृष्टिकोण

श्री लोक रंजन, सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (मो डोनर) द्वारा एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विभिन्न एजेंसियां भारत भर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के सुदूर और भौगोलिक रूप से कठोर इलाकों में अपनी-अपनी पहल का सफल कार्यान्वयन निश्चित रूप से अधिक संतोषजनक और प्रभावशाली होगा। श्री रंजन ने संभव (SAMBHAV) के बारे में भी जानकारी दी जो एक मिशन मोड परियोजना है, सरकार की मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत आदर्श ग्राम पंचायतों की संतृप्ति के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है ताकि चयनित ग्राम पंचायतों में केपीआई राज्य/राष्ट्रीय औसत हासिल कर सकें। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की कमी, आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि की अनुपलब्धता, कठिन इलाके और कम वितरित आबादी, और सख्त वन नियम, आंदोलन और स्थानीय मुद्दे पूर्वोत्तर के ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियाँ हैं जो लक्षित विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं। बाधाओं के बावजूद, इस क्षेत्र में कई सफलता की कहानियां हैं जो आशा की किरण प्रदान करती हैं। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन में ड्रोन का उपयोग करने की मेडिसिंस फ्रॉम द स्काई पायलट परियोजना जैसी प्रमुख सफलता की कहानियां; मेघालय में ऊर्जा पहुंच में सुधार और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सौर ऊर्जा पहल को बहुत जोर से चलाना; स्टार एजुकेशन मणिपुर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और डेटा-संचालित

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

प्लेटफॉर्म और नूतन दिशा पहल, पूरे त्रिपुरा में शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए शिक्षकों की एक टीम को अकादमिक नेताओं के रूप में पहचानने पर केंद्रित है।

श्री रंजन के संबोधन के बाद, देश भर से ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को उनके द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न अभिनव और उत्थान उपायों को साझा करने के लिए बुलाया गया था।

निम्नलिखित खंड में इस सत्र की मुख्य बातें शामिल हैं:

i. नारियन वेस्ट गांव, जम्मू और कश्मीर के जीपी प्रतिनिधि ने उल्लेख किया कि पंचायत ने अपने क्षेत्र में कचरा पृथक्करण और सोक पिट सुविधा को सफलतापूर्वक लागू/शुरू किया है। वे निवासियों को बुने हुए बैग उपलब्ध कराने के रूप में स्थानीय एसएचजी के सहयोग से अपने जीपी को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। वे चीड़ के पेड़ों से बने उत्पादों को भी सक्रिय रूप से बेच रहे हैं। जीपी कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सौर पंपों और सौर प्रकाश व्यवस्था का लाभ उठाने के संभावित रास्ते तलाश रहा है। जीपी ग्राम बाजार आयोजित करने की भी योजना बना रहा है, जिसमें आगे की आर्थिक उन्नति के लिए स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।

वे

जल संचयन में सफल रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत उत्कृष्ट/बेहतर सड़क निर्माण प्रदर्शन से प्राप्त पुरस्कार राशि से, ग्राम पंचायत स्टालों का निर्माण कर रही है और उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिए स्थानीय आबादी को पुरस्कृत कर रही है, जिससे अतिरिक्त रोजगार पैदा हो रहा है।

ii. बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के जीपी प्रतिनिधि ने कहा कि उनके क्षेत्र में पानी की अत्यधिक कमी की स्थिति को हल करने के लिए रिवरफ्रंट क्षेत्रों में रिबोरिंग कार्य किया गया था। कोविड-19 में शत-प्रतिशत साक्षरता के उद्देश्य से नि:शुल्क कोचिंग सेंटर संचालित किए गए। ग्राम पंचायत को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए

घरों से एकत्र किए गए बेकार कपड़ों से बने बुने हुए बैग निवासियों को वितरित किए गए। जीपी में मॉडल स्मार्ट स्कूल संचालन भी प्रगति पर है।

iii. राजपुर, हाथरस, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत प्रतिनिधि ने साझा किया कि शिक्षा, सरकारी योजनाओं और किसी भी अन्य शिकायतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत में साप्ताहिक महिला शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए जीपी में प्लास्टिक बायबैक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। भौतिक क्षति, कनेक्टिविटी मुद्दों और अन्य परिचालन चुनौतियों के प्रतिरोध के परीक्षण के लिए चुनिंदा स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। स्कूलों और आंगनबाड़ियों जैसे सार्वजनिक संस्थानों में हाथ धोने को बढ़ावा देने के लिए फिक्की और यूनिसेफ के सहयोग से हैप्पी टैप्स लगाए जा रहे हैं। परित्यक्त भवनों को सार्वजनिक पुस्तकालयों के रूप में पुनर्निर्मित किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षकों की उपलब्धता के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सुविधा होती है। जीपी में सार्वजनिक दाह संस्कार की सुविधा की व्यवस्था भी गई है। जीपी मुफ्त वाई-फाई, संपूर्ण सीसीटीवी कवरेज, किसान मित्र और बैंकिंग संवाददाता सखी जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना बना रहा है ताकि जीपी में स्थितियों को और बेहतर बनाया जा सके।

जीपी प्रतिनिधियों के साथ प्रेरक सत्र के बाद, श्री आलोक प्रेम नागर, संयुक्त सचिव (गवर्नेंस), पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने दर्शकों के लिए वर्तमान और पिछले दिन की घटनाओं का सारांश दिया। श्री नागर ने स्मार्ट पंचायत विकसित/गठित करने के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण के महत्व को भी रेखांकित किया।

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

इसके बाद, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री का विदाई भाषण। अपने संबोधन में श्री पाटिल ने कहा कि गांव को स्मार्ट बनाने से पहले सरपंचों को स्मार्ट बनाना चाहिए और गांव को स्मार्ट बनाना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के अगले आयोजन में, ग्राम पंचायत प्रमुखों को अपने विचार साझा करने और दर्शकों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण समय आवंटित किया जाना चाहिए। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आईसीटी, इंटरनेट, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का लाभ उठाकर जमीनी स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण कल्याण की लंबी उम्र/यात्रा के बारे में बात की। उन्होंने मांग-आपूर्ति प्रबंधन जैसी चुनौतियों पर जोर दिया, जिनका डिजिटल बुनियादी ढांचे, बढ़ती आबादी और अपरिहार्य तेजी से शहरीकरण के अनुकूल होने के दौरान पंचायतों को सामना करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रिया को क्रियान्वित करने और निगरानी करने के लिए एक रणनीति/मॉडल तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि क्लस्टर दृष्टिकोण, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, विनियमों और प्रबंधन के आधार पर नागरिकों की भागीदारी के आधार पर विशेष रूप से डिजाइन किया गया उपयुक्त ढांचा अगली पीढ़ी के स्मार्ट गांवों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंत में, श्री पाटिल ने इस तथ्य को दोहराया कि जहां एक गांव को स्मार्ट बनाना आसान काम नहीं है, वहीं सभी महत्वपूर्ण हितधारकों के सहयोगात्मक दृष्टिकोण के साथ यह असंभव भी नहीं है।

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

ज. सम्मेलन से प्राप्त मुख्य तथ्य

i. ग्रामीण नागरिकों की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, जो न केवल सशक्त ग्रामीण समुदायों का निर्माण करेगा, बल्कि स्मार्ट ग्राम पंचायतों को भी गति प्रदान करेगा।

ii. डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाकर ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए परियोजनाएं शुरू करने के लिए ग्राम पंचायतों, राज्य और जिला पंचायती राज अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और उद्योगों की ओर से सामुदायिक भागीदारी और प्रयास।

iii. ग्राम सहायकों के रूप में वीएलई जैसी प्रमुख पहलों से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अंतर-राज्य, इंट्रा स्टेट, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, इंट्रा ब्लॉक आधार पर जीपी के बीच सक्रिय ज्ञान साझा करना; आधारशिला, यूपी में बीसी सखियां, कर्नाटक में डिजिटल लाइब्रेरी पहल और केरल का आईएलजीएमएस

iv. आईसीटी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए टावरों की स्थापना के लिए संभावित स्थलों की पहचान के लिए तरंग संचार जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग

v. जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तकनीकी सहायता के लिए नाबार्ड जैसे वित्तीय संस्थानों और आईआईटी, टेरी, एनआईआरडीपीआर, और आईआईएससी जैसे शैक्षणिक संस्थानों के साथ सक्रिय सहयोग

vi. पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए GeM और eSPI-PFMS जैसे प्लेटफार्मों का अनिवार्य उपयोग

vii. राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए राज्यों द्वारा एक विशिष्ट रोडमैप तैयार करना।

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

अनुबंध I- 'स्मार्ट ग्राम पंचायतें : ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना; लीविंग नो वन बिहाइंड'

सम्मेलन: मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम

दिनांक: 15-16 सितंबर, 2022

स्थान: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान , लखनऊ उत्तर प्रदेश

पहला दिन (15 सितंबर, 2022)

सत्र	टाइम स्लॉट	विवरण	वक्तागण
पंजीकरण	**11:00 - 10:00 पूर्वाह्न**	**प्रतिभागियों का पंजीकरण और चाय**	
क. उद्घाटन सत्र	11.00 बजे पूर्वाह्न	माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का आगमन ; माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज; और माननीय, पंचायती राज राज्य मंत्री कार्यक्रम स्थल पर	
	11:05 -11:00 पूर्वाह्न	स्मार्ट ग्राम पंचायत प्रदर्शनी का अवलोकन	
	11:06 -11:05 पूर्वाह्न	अंगवस्त्र की प्रस्तुति और माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश; माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज; और माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री का स्वागत	सचिव एमओपीआर ,
	11:09 - 11:06 पूर्वाह्न	स्वागत भाषण	सचिव एमओपीआर ,
	11:15 -11:09 पूर्वाह्न	एडु टेक और टेलीमेडिसिन द्वारा प्रस्तुतीकरण हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों में अपेक्षित- (मिनट 3 प्रत्येक में) परिवर्तनों पर कंपनियां	
	11:20 -11:15 पूर्वाह्न	श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, पंचायती राज राज्य मंत्री का संबोधन	
	11:32 - 11:20 पूर्वाह्न	श्री गिरिराज राज सिंह, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का संबोधन	
	11:33 -11:32 पूर्वाह्न	पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (पीआरआई), उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार ई-लर्निंग मॉड्यूल का शुभारंभ	

	11:34 -11:33 पूर्वाह्न	सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर एक (एलएसडीजी) पुस्तक का विमोचन	
	11:37 -11:34 पूर्वाह्न	उत्तर प्रदेश में स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर एक लघु फिल्म	
	11:47 - 11:37 पूर्वाह्न	माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन	
	11:4712.00 - दोपहर	माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा मंत्रियों के , किट (ओडीओपी) प्रतिनिधिमंडल को एक जिला एक उत्पाद की प्रस्तुति	
मॉडरेटर/प्रतिवेदक/रिपोर्टयर: श्री अमरजीत सिन्हा , पूर्व सचिव, आरडी और पीआर **रिपोर्टियर : सुश्री कर्णिका कौशिक, सलाहकार/श्री. मोहित राव, सलाहकार**			
बी स्मार्ट ग्राम पंचायतें और कनेक्टिविटी	12:00 बजे दोपहर 12:15 अपराह्न	उत्तर प्रदेश स्मार्ट पंचायतों की पहल	श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
	12:30 - 12:15 अपराह्न	स्मार्ट शिक्षा, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना	श्री विनीत नायर, संपर्क फाउंडेशन
	12:45 - 12:30 अपराह्न	डिजीगांव	श्री ऋषिकेश पाटनकर , सीओओ, सीएससी- एसपीवी
	1:00 - 12:45 अपराह्न	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता	श्री केसी झा, सलाहकार, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
	1:15 -1:00 अपराह्न	एकीकृत स्थानीय शासन प्रबंधन प्रणाली (आईएलजीएमएस), केरल	पंचायती राज विभाग, केरल
	1:30 -1:15 अपराह्न	स्मार्ट विलेज पंचायतों के विकास का वित्तपोषण	श्री एसके डोरा, नाबार्डी
	1:30 - 2:15 अपराह्न	**दोपहर का भोजनावकाश/लंच ब्रेक**	
ख स्मार्ट गांव पंचायत और	2:30 - 2:15 अपराह्न	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल नेटवर्क कवरेज बढ़ाना	श्री विक्रम तेवतिया, डीडीजी, सीओएआई

कनेक्टिविटी (जारी..)	2:45 - 2:30 अपराह्न	कुशल शासन और आर्थिक विकास के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी	श्री प्रणय: पाठक, रिलायंस जियो
	3:00 - 2:45 अपराह्न	ग्रामीण संपर्क के लिए तकनीकी विकल्प	प्रो. कृष्णा सिरोही , प्रैक्टिस प्रोफेसर, आईआईटी दिल्ली
	3:15 -3:00 अपराह्न	स्मार्ट ग्राम पंचायतें की भूमिका स्मार्ट में कनेक्टिविटी	बीबीएनएल के प्रतिनिधि
	3:30 - 3:15 अपराह्न	प्रश्नोत्तर सत्र; मॉडरेटर द्वारा सारांश	
मॉडरेटर/प्रतिवेदक: श्री मदन पादकी , सीईओ और संस्थापक, 1ब्रिज **रिपोर्टर/प्रतिवेदक : श्री श्लोकार्थी त्रिवेदी , सलाहकार/सुश्री रितुपर्णा घोष पॉल, सलाहकार**			
ग कुशल आईसीटी श्रमशक्ति	03:45 -03:30 अपराह्न	उन्नत भारत अभियान	प्रो. वी के विजय, आईआईटी दिल्ली
	04:00 -03:45 अपराह्न	डिजिटल पुस्तकालय, कर्नाटक	पंचायत प्रतिनिधि, कर्नाटक
	04:15 -04:00 अपराह्न	अपस्किलिंग रूरल इंडिया	1. श्री वामली उदयगिरी, सीईओ, हेसा ग्लोबल 2. श्री शौयेन्दु मेडडा, सीईओ, डील शेयर
	04:30 -04:15 अपराह्न	ग्रामीण उद्यमिता का सिम्बाक्वार्ट्ज-टंगरा बिजनेस मॉडल	सुश्री मंदीप कौर , सिम्बा क्वार्ट्ज
	4:45 -4:30 अपराह्न	प्रश्नोत्तर सत्र; मॉडरेटर द्वारा सारांश	
मॉडरेटर: श्री अभय भाकरे , डीजी, बीईई **रिपोर्टर/प्रतिवेदक : श्री सुशांत सुधीर , सलाहकार/श्री. गर्वित त्रिवेदी , सलाहकार**			
डी स्मार्ट एनर्जी	5:00 -4:45 अपराह्न	ग्रामीण क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा को अपनाने में चुनौतियां	सुश्री पवित्रा सिन्हा, शक्ति फाउंडेशन

	5:15 -5:00 अपराह्न	ओदान्थुराई ग्राम पंचायत , तमिलनाडु द्वारा अनुभव साझा करना	ओदंथुरई ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, तमिलनाडु
	5:30 -5:15 अपराह्न	कम लागत और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य ऊर्जा समाधान	श्री शिरीष गरुड़, अक्षय ऊर्जा टेक्नोलॉजी, टेरी
	5:45 -5:30 अपराह्न	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार की पहल	श्री जे के जेठानी , वैज्ञानिक, एमएनआरई
	6:00 -5:45 अपराह्न	प्रश्नोत्तर सत्र; मॉडरेटर द्वारा सारांश	
अपराह्न 6:30 - 6:00		**हाई टी**	

दूसरा दिन (16 सितंबर 2022)

सत्र	**टाइम स्लॉट**	**विवरण**	**वक्तागण**
पंजीकरण	**पूर्वाह्न 10:00 -9:00**	**प्रतिभागियों का पंजीकरण और चाय**	
मॉडरेटर: श्री आलोक अग्रवाल , पार्टनर, डेलॉयट **प्रतिवेदक : श्री सुबोध गुर्जर , सलाहकार/श्री. प्रेरित सारस्वत , सलाहकार**			
ङ स्मार्ट कृषि स्मार्ट _ पर्यावरण	10:00- 10:15 पूर्वाह्न	कृषि में परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां	श्री अभय पारीक, लीड, चौथा औद्योगिक कृषि विश्व आर्थिक मंच के लिए क्रांति
	10:15 - 10:30 पूर्वाह्न	फसल अवशेष प्रबंधन	देबाशीष बिस्वास , साथी, डेलॉइट
	10:30 - 10:45 पूर्वाह्न	स्मार्ट कृषि अवसर	श्री अर्जुन वेंकटरमन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
	10:45 - 11:00 पूर्वाह्न	भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर एक जिला	श्री मिन्हाज आलम, अपर सचिव, खाद्य मंत्रालय

		एक उत्पाद योजना का प्रभाव	प्रसंस्करण उद्योग
	11:00 - 11:15 पूर्वाह्न	ग्रामीण बाजार	डॉ. केतकी बापट , प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
	11:15 - 11:30 पूर्वाह्न	ग्रामीण ई-कॉमर्स में अवसर	श्री शिरीश जोशी, मुख्य व्यवसाय अधिकारी, डिजिटल कामर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)
	11:30 - 11:45 पूर्वाह्न	ई- चौपाल मॉडल- भारतीय कृषि व्यवसाय क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना	श्री कुमार प्रणेश , क्षेत्रीय प्रमुख, आईटीसी
	11:45 पूर्वाह्न - 12:00 दोपहर	स्मार्ट कृषि में सर्वोत्तम अभ्यास	श्री अनुज अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईआई यंग इंडियन, उत्तर प्रदेश
	12:15 -दोपहर 12:00 अपराह्न	मीनांगडी पंचायत, केरल- कार्बन तटस्थता की ओर	• श्री केई विनयन , अध्यक्ष, मीनांगडी ग्राम पंचायत • सुश्री बीना विजयन, सदस्य, सुल्तान बाथेरी ब्लॉक पंचायत वायनाड
	12:15 - 12:30 अपराह्न	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्यावरण की सर्वोत्तम प्रथाएं/पद्धतियां	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रतिनिधि
	12:30 - 12:45 अपराह्न	प्रश्नोत्तर सत्र; मॉडरेटर द्वारा सारांश	
1:00 - 2:00 अपराह्न		**लंच ब्रैक**	
मॉडरेटर: डॉ इंदु भूषण, पूर्व सीईओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण **रिपोर्टर/प्रतिवेदक : श्री मोहित गुप्ता, सलाहकार / श्री तपिन भाटी, सलाहकार**			

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

एफ स्मार्ट स्वास्थ्य	2:00 - 2:15 अपराह्न	नागरिक केंद्रित हेल्थकेयर लीवरेजिंग आईटी और संबद्ध/सहायक प्रौद्योगिकियों	श्री अमित सिंह, कार्यकारी निदेशक, डेलॉयट
	2:15 - 2:30 अपराह्न	इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश की पहल	श्री जे निवास, आयुक्त एच एंड एफडब्ल्यू, आंध्र प्रदेश
	2:30 - 2:45 अपराह्न	ग्रामीण स्वास्थ्य की तैयारी और बुनियादी ढांचे का विकास	श्री श्यामल सांतरा, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन
	2:45 - 3:00 अपराह्न	प्रश्नोत्तर सत्र; मॉडरेटर द्वारा सारांश	
जी. उत्तर-पूर्व क्षेत्र उन्मुख दृष्टिकोण	3:00 - 3:15 अपराह्न	पूर्वोत्तर भारत में स्मार्ट विलेज पंचायतों की दिशा में सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी	श्री लोक रंजन, सचिव, पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय
एच. समापन सत्र	3:15 - 3:30 अपराह्न	मोडरेटेड चर्चा सत्र (प्रश्न और उत्तर)	संयुक्त सचिव (गवर्नेंस), एमओपीआर
	3:30- 3:40 अपराह्न	समापन भाषण	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री
	3:40- 3:55 अपराह्न	धन्यवाद प्रस्ताव	निदेशक उत्तर ,पंचायती राज , प्रदेश
4:00 - 4:30 अपराह्न		**हाई टी**	

15-16 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित स्मार्ट ग्राम पंचायतों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की विस्तृत कार्यवाही

अनुबंध-II राष्ट्रीय सम्मेलन में मोडरेटर और वक्ताओं की संक्षिप्त रूपरेखा

श्री अमरजीत सिन्हा, पूर्व सचिव, आरडी और पीआर

श्री अमरजीत सिन्हा बिहार कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के सदस्य हैं। वे प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हैं। उन्हें सरकार में मुख्यतः ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में 38 वर्षों का अनुभव है। उन्हें सर्व शिक्षा अभियान (सार्वभौमिक शिक्षा के लिए भारत का मुख्य कार्यक्रम), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को डिजाइन करने में और आजीविका, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल, शहरी विकास और सड़क निर्माण को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों में शासन सुधार लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

श्री मनोज कुमार सिंह, एसीएस, पीआरडी

psecuppanchraj@nic.in

श्री मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। वह उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत और स्मार्ट सिटी जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के मिशन निदेशक थे। उन्हें प्रयागराज में महाकुंभ-2013 और कुंभ 2019 के सफल आयोजन के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री से प्रशंसा पत्री मिली है।

श्री विनीत नायर, संस्थापक, संपर्क फाउंडेशन

श्री प्रदीप राणा, संपर्क फाउंडेशन:pradeeprana@samparkfoundation.org

विनीत नायर संपर्क फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के पूर्व उपाध्यक्ष और सीईओ और अत्यधिक प्रशंसित प्रबंधन बेस्टसेलर "कर्मचारी पहले, ग्राहक बाद में: पारंपरिक प्रबंधन अपसाइड डाउन" के लेखक हैं (हार्वर्ड बिजनेस प्रेस, जून 2010)। विनीत

को फॉर्च्यून पत्रिका ने अपनी पहली वैश्विक कार्यकारी ड्रीम टीम के लिए चुना था और उन्हें कुलीन विचारकों की 50 सूची में स्थान मिला था। उनके अभिनव, परिवर्तनकारी विचारों को स्वर्गीय सी के प्रहलाद, टॉम पीटर्स, गैरी हैमेल और राम चरण जैसे प्रभावशाली लोगों से भरपूर प्रशंसा मिली है।

श्री ऋषिकेश पाटनकर, सीओओ सीएससी-एसपीवी

rishikesh@csc.gov.in

ऋषिकेश पाटनकर को आईसीटी डोमेन में 21 वर्षों से अधिक का अनुभव है जिसमें राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, विदेशों में शीर्ष विश्वविद्यालयों और भारतीय नौसेना में कार्य करना शामिल है। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। वे नेट क्वालिफाइड भी हैं। वे शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कई परियोजनाओं का प्रबंधन करते हैं। उनके शोधपत्र प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। वह कार्यान्वयन पक्ष से क्रमशः एमईआईटीवाई और न्याय विभाग के तहत पीएमजीदिशा और टेली-लॉ जैसी परियोजनाओं का नेतृत्व करते हैं। वे सीएससी अकादमी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

श्री के सी झा, सलाहकार, जीईएम

kc.jha@gem.gov.in

श्री कुमार चंद्रहास झा वर्तमान में एक सलाहकार-व्यावसायिक कार्य और एकीकरण और जेम के पूर्व अपर सीईओ हैं। वह अनुसंधान आधारित कंप्यूटर एडेड डिजाइन और सिमुलेशन में माहिर हैं। वह वर्तमान में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ ईआरपी एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि व्यावसायिक कार्यों की देखरेख और जेएम पर निर्णय समर्थन प्रणाली के निष्पादन और कार्यान्वयन की भी देखरेख कर रहे हैं।

विनोद कुमार के, पंचायतों के सहायक निदेशक, केरल

श्री विनोद कुमार के पंचायतों के सहायक निदेशक, केरल ने 2009 के दौरान सुशासन और कुल गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर बेहतर सेवा वितरण और कुशल कार्यालय प्रबंधन के लिए केरल की सभी ग्राम पंचायतों में फ्रंट ऑफिस प्रबंधन को डिजाइन और कार्यान्वित किया। एक कुशल और नागरिक केंद्रित सिविल सेवा की

दिशा में योगदान के लिए 2020 में एलएसजीडी द्वारा यूनिक टैलेंट अवार्ड से सम्मानित किये गए। विभाग में योगदान के लिए 2019 में पंचायत निदेशक द्वारा गुड सर्विस एंट्री से सम्मानित किया गया।

श्री एस के डोरा, नाबार्ड

श्री संजय कुमार डोरा नाबार्ड उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक हैं। ग्रामीण विकास बैंकिंग में 3 दशकों से अधिक के कार्य अनुभव के साथ एक विकासात्मक बैंकर, श्री डोरा ने पिछले 34 वर्षों में नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न पदों पर काम किया है। श्री एस के डोरा भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) की शासी परिषद के सदस्य भी थे।

श्री विक्रम तेवतिया, उप महानिदेशक, सीओएआई

ddg@coai.in

विक्रम सीओएआई के उप महानिदेशक हैं। यह दूरसंचार, ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाओं के लिए भारत का अग्रणी उद्योग संघ है। वे नियामक और नीतिगत मामलों के लिए ICT उद्योग के नेताओं और DoT, MeitY, TRAI और अन्य सरकारी कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक रूप से सम्पर्क में रहते हैं। वे मुख्य साइबर सुरक्षा समन्वयक की अध्यक्षता में साइबर सुरक्षा पर संयुक्त कार्य समूह के सदस्य हैं। राष्ट्रीय उद्योग संघों - सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, और टीएसडीएसआई समितियां के एक सक्रिय सदस्य हैं। वे आईटीयू, एपीटी आदि द्वारा आयोजित कई अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं/सम्मेलनों में भाग लेते हैं।

श्री प्रणय पाठक, रिलायंस जियो

pranay.p.pathak@ril.com

श्री प्रणय पाठक यूपी (ई) सर्कल में रिलायंस जियो इंफोकॉम के सीईओ हैं और दूरसंचार सेवाओं के रोलआउट और बिजनेस ऑपरेशंस के प्रमुख हैं।

प्रोफेसर कृष्णा सिरोही, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, आईआईटी दिल्ली

ksirohi@dbst.iitd.ac.in

प्रो. कृष्णा सिरोही आईआईटी दिल्ली में भारती स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में प्रैक्टिस के प्रोफेसर हैं। उनके पास दूरसंचार और रक्षा संचार उत्पाद डिजाइन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का 33

वर्षों का अनुभव है। उन्हें दूरसंचार/आईसीटी मानकीकरण गतिविधियों का लंबा अनुभव है। अपने औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और नेतृत्व की भूमिकाओं में, वह इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सीडीओटी) [मोबाइल टेक्नोलॉजीज डिवीजन के प्रमुख] और विहान नेटवर्क्स लिमिटेड (वीएनएल) से जुड़े थे। [सीटीओ के रूप में मोबाइल टेलीकॉम आर एंड डी और निर्माण कंपनी की स्थापना की]। प्रो. सिरोही वर्तमान में अनुसंधान अनुवाद और क्षेत्र-तैनाती योग्य उत्पाद विकास की दिशा में आईआईटी दिल्ली में '5जी एंड बियॉन्ड' आरएंडडी और इनक्यूबेशन फैसिलिटी डेवलपमेंट प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं।

अतुल शर्मा, बीबीएनएल
श्री अतुल शर्मा बीबीएनएल लखनऊ के प्रधान महाप्रबंधक (परियोजना) हैं

pgmbbnlupe@gmail.com

श्री मदन पदाकी, 1ब्रिज सीईओ और संस्थापक,
वह 1ब्रिज के संस्थापक और सीईओ हैं, जो एक सहायक-वाणिज्य मंच है जो हमारे उभरते बाजारों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं और आकांक्षात्मक उत्पादों को वितरित करता है जैसे कि ग्रामीण ग्राहकों के लिए बिक्री, वित्तपोषण और अंतिम-छोर तक वितरण नेटवर्क को सक्षम करते हुए ग्रामीण ग्राहकों के लिए पहुंच, पसंद और सुविधा अंतराल को पाटना। आज, 1ब्रिज दक्षिण और पूर्वी भारत के 77+ जिलों में मौजूद है और इसके 12,500+ से अधिक ग्रामीण उद्यमी अपने उपभोक्ताओं को सेवा देने में लगे हुए हैं। 1ब्रिज को सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में मान्यता दी गई थी और माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2022 में राष्ट्र के नाम अपने मन की बात संबोधन में इसके अग्रणी कार्य के लिए प्रकाश डाला गया। मदन ने 1वर्स की भी सह-स्थापना की है जिसका उद्देश्य भौतिक और मेटा दुनिया के बीच की दूरी को मूल रूप से पाटना है, तथा मेटावर्स में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गये उत्पादों / सेवाओं के अनुभव के तरीके में क्रांति लाने के लिए वास्तव में एक अनूठा मंच बनाना है। ।

madan@1bridge.one

डॉ दिव्या खट्टर, उन्नत भारत अभियान

divyakhatter.uba@gmail.com

दिव्या खट्टर उन्नत भारत अभियान की प्रधान परियोजना वैज्ञानिक हैं।

डॉ शोभा आनंद रेड्डी ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, कर्नाटक सरकार

parisarashobha@gmail.com

डॉ. शोभा आनंद रेड्डी, वर्तमान में पंचायत राज विभाग के साथ भारतीय प्रशासनिक फैलोशिप कार्यक्रम के तहत विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। वह शिक्षा, क्षमता निर्माण, अनुसंधान, अभ्यास, वकालत और प्रशासन में 20 से अधिक वर्षों के विविध अनुभव के साथ एक पर्यावरण वैज्ञानिक हैं।

श्री प्रसन्ना वी.आर, सीईओ, शिक्षा फाउंडेशन

prasanna@sikshana.org

प्रसन्ना वी आर 2007 से शिक्षा फाउंडेशन के साथ हैं और उन्होंने कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों में सीखने को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को बढ़ाया है और 5 अन्य राज्यों के हजारों स्कूलों में भी चलाया जा रहा है। वह वर्तमान में ग्राम डिजी विकास कार्यक्रम को कर्नाटक के सभी 6000+ ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने के प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षा से पहले, 10 साल तक सॉफ्टरेन्ड्स इंक. यूएसए की संस्थापक और सीईओ थ।

श्री वामसी उदयगिरी, सीईओ, हेसा ग्लोबल

ceo@hesaglobal.com

श्री वामसी उदयगिरी एचईएसए ग्लोबल का नेतृत्व कर रहे हैं जो ग्रामीण भारत को कॉरपोरेट्स, बैंकों, एनबीएफसी और शहरों से जोड़ रहे हैं ताकि ग्रामीण उपभोक्ता न केवल उत्पाद खरीद सकें बल्कि अपने उत्पादों को बेच भी सकें। वे ग्रामीण भारत को लास्ट माइल फिजिकल और डिजिटल कनेक्ट प्रदान करके ग्रामीण वाणिज्य को फिर से परिभाषित कर रहे हैं। वे एकीकृत बी2बी मार्केटप्लेस एग्रीगेट हैं और जिसके दो पहलू को जोड़ते हैं और दरवाजे तक पहुंच के साथ खरीदारी और बिक्री को सक्षम बनाता है। उनका "फिजिटल", (ग्राम-स्तरीय उद्यमियों का एक भौतिक नेटवर्क, वीएलई) प्रत्येक गांव में

एक डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा सहायता प्रदान करता है) दृष्टिकोण दो प्रमुख पहलू हैं जो व्यवसायों को अपने ग्रामीण लक्षित दर्शक इलाकों तक पहुंचने, प्रदर्शित करने, प्रदर्शित करने और लेनदेन करने में सक्षम बना रहे हैं।

श्री सौर्जेयेंदु मेद्दा, सीईओ, Dealshare.in

sourjyendu@dealshare.in

सौरज्येंदु मेद्दा एक अनुभवी व्यावसायिक पेशेवर हैं, जिनका उपभोक्ता ब्रांड बनाने का दो दशकों से अधिक का अनुभव है। मार्केटिंग, सीआरएम, मूल्य निर्धारण और संचालन सहित व्यवसाय प्रबंधन के सभी पहलुओं में उनका एक प्रतिष्ठित ट्रैक रिकॉर्ड है। डीलशेयर, एक सोशल ई-कॉमर्स स्टार्ट-अप के संस्थापक सदस्यों में से एक के रूप में, उन्होंने ; व्हाट्सएप-पहली सामाजिक पौरूष अवधारणा का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर बाजार के उद्देश्य से भारत के हृदय क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से विघटनकारी ई-कॉमर्स अवसर को जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।

सुश्री मंदीप कौर, सिम्बा क्वार्ट्ज

office@mandeepkaurtangra.com

पिछले दस वर्षों से, मनदीप पंजाब के ग्रामीण इलाकों में एक आईटी गांव स्थापित करके "बदलते जीवन" के दृष्टिकोण पर काम कर रही हैं। उसने सफलतापूर्वक 120+ कर्मचारियों की एक टीम बनाई है। वह आईटी गांवों की स्थापना और गांव से शहर प्रवास, बेरोजगारी और ब्रेन ड्रेन पर अंकुश लगाने के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध है। उनका मानना है कि "टांगरा बिजनेस मॉडल" को दोहराया जा सकता है और न केवल आईटी में बल्कि विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भारत में लाखों व्हाइट-कॉलर नौकरियां पैदा कर सकता है। अपने परोपकारी कार्यों के तहत, उन्होंने 500+ शू गिविंग और फूड शेयरिंग अभियानों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। उनके उद्यम को एसोचैम इंडिया द्वारा "द अपकमिंग स्टार्ट-अप ऑफ द ईयर 2016" से सम्मानित किया गया है और वर्ष 2019 में सामाजिक उद्यमिता के लिए एक एलुमिनी पुरस्कार प्राप्त किया है। वह एलपीयू के लिए वर्ष 2020 के लिए एक विश्वविद्यालय छात्र राजदूत भी थी। वह वर्तमान में वर्ष 2022 के लिए "द एलपीयू एलुमनी एंटरप्रेन्योर क्लब" और "अमृतसर फाउंडर्स" की अध्यक्ष हैं।

श्री अशोक श्रीवास्तव, यूपीनेडा

श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी है

सुश्री पवित्रा सिन्हा, शक्ति फाउंडेशन

Pavithra@shaktifoundation.in

पवित्रा शक्ति में क्लीन पावर प्रोग्राम में काम करती है। साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय (यूके) से ऊर्जा और स्थिरता में मास्टर डिग्री और विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल्स में बीई के साथ, पवित्रा डेटा विश्लेषण और प्रयोगात्मक विधियों, इमारतों और शहरों के जलवायु डिजाइन, जीआईएस और बायोएनेर्जी में माहिर हैं। शक्ति में आने से पहले पवित्रा ने शक्ति के साथ छह महीने की इंटर्नशिप पूरी की।

ओदंथुरई ग्राम पंचायत, तमिलनाडु का एक प्रतिनिधि

ओदंथुरई ग्राम पंचायत, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु, ग्राम पंचायत द्वारा अक्षय ऊर्जा को अपनाने में अपने अभूतपूर्व कार्य के कारण स्व-शासन के रोल मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। ओदंथुरई ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने अक्षय ऊर्जा को अपनाने में अपने प्रयासों और उपलब्धियों का संक्षिप्त सारांश दिया।

श्री शिरीष गरुड़, अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, टेरी

श्री शिरीष एस गरुड़, द रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) दिल्ली में निदेशक और वरिष्ठ फेलो है। उन्हें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। वह अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर, पवन), ऊर्जा योजना और नवीकरणीय ऊर्जा नीति अध्ययनों में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। उनके पास सौर और पवन संसाधन मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन, और नीति और नियामक अध्ययन में समृद्ध अनुभव है।

श्री जे के जेठानी, वैज्ञानिक, एमएनआरई

jethani.jk@nic.in

वर्तमान में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत, वे अक्षय ऊर्जा से संबंधित नीति और विनियमों के निर्माण, राष्ट्रीय सौर मिशन के लिए कार्यान्वयन ढांचे की तैयारी, हवा में बोली लगाने की शुरुआत से जुड़े रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र, पवन ऊर्जा खरीद के लिए बोली दिशानिर्देश और योजनाएं, रूफटॉप सौर और ऑफ-ग्रिड सौर पीवी और थर्मल अनुप्रयोगों का कार्यान्वयन, पीएम-कुसुम योजना का निर्माण और इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा, आदि। अक्षय ऊर्जा एजेंसियों के संघ के कार्यकारी निदेशक के रूप में राज्यों (क्षेत्रों) ने क्षेत्रों के कामकाज को पुनर्जीवित किया।

श्री आलोक अग्रवाल, पार्टनर डेलॉयट

aloagarwal@deloitte.com

आलोक डेलॉइट के साथ एक भागीदार है और कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। उनके पास विकास परामर्श का बाईस वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने विश्व बैंक, FCDO, ADB, GIZ, आदि द्वारा वित्त पोषित और साथ ही विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की संस्थाओं और निजी क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित और / या किए गए विभिन्न दाता-वित्त पोषित कार्यों में कृषि / ग्रामीण विकास परामर्श असाइनमेंट में बड़े पैमाने पर काम किया है।

श्री अभय पारीक, अग्रणी, कृषि के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति, विश्व आर्थिक मंच

Abhay.Pareek@weforum.org

अभय को कृषि और विकास वित्त पर केंद्रित बहु-हितधारक पहलों के प्रबंधन का 14 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वे विश्व आर्थिक मंच, भारत में कृषि के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए लीड/अग्रणी के रूप में काम कर रहे हैं। फोरम में वह सरकार, उद्योग, किसान संगठनों और स्टार्ट-अप के समन्वय में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से डिजिटल कृषि को बढ़ाने के लिए पहल करने के लिए जिम्मेदार हैं। विश्व आर्थिक मंच से पहले, अभय ने नेपाल,

चीन, फिलीपींस और भारत में विभिन्न क्षमताओं में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष और एमएससी परामर्श के साथ काम किया।

श्री देबाशीष विश्वास, पार्टनर, डेलॉइट

debiswas@DELOITTE.com

देबाशीष डेलॉइट के परामर्श अभ्यास/मामलों के भागीदार हैं और रणनीति और व्यवसाय डिजाइन समूह का हिस्सा हैं। उन्हें कई क्षेत्रों में परामर्श करने का लगभग 20 वर्षों का अनुभव है। भारत के अलावा, उनका अनुभव संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बोत्सवाना, सऊदी अरब, कतर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में फैला है। उनके ग्राहकों में सरकारी मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, डोनर/बहु-पक्षीय एजेंसियां, फाउंडेशन, सरकारी संस्थान, निजी क्षेत्र आदि शामिल हैं। देबाशीष ने अपना फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (डॉक्टरेट प्रोग्राम) आईआईएम अहमदाबाद से किया।

श्री अर्जुन वेंकटरमन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन

Arjun.Venkatraman@gatesfoundation.org

श्री अर्जुन वेंकटरमन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इंडिया कंट्री ऑफिस का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह लैंगिक समानता, आजीविका, कृषि, वाश और वित्तीय सेवाओं से संबंधित डिजिटल कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

श्री मिन्हाज आलम, अपर सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

minhaj@ias.nic.in

श्री मिन्हाज आलम, केरल कैडर के 1996 बैच के हैं, जिन्होंने संयुक्त सचिव के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में जाने से पहले केरल और बिहार में व्यापक रूप से सेवा की। उन्हें हाल ही में अपक सचिव, MoFPI के रूप में पदोन्नत किया गया है और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (PM FME) के पीएम औपचारिककरण के पीछे प्रेरक शक्ति है।

डॉ. केतकी बापट, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय

ketakibapat@gmail.com

डॉ. केतकी बापट, वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय में वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। वह रेडियोफार्मास्युटिकल्स डिवीजन में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से जुड़ी हुई हैं और पीएसए कार्यालय में आरयूटीएजी (ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह) जैसी विभिन्न पहलों में योगदान दिया है।

श्री शिरीश जोशी, मुख्य व्यवसाय अधिकारी, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी)

shireesh@ondc.org

श्री श्रीश जोशी उभरते एशियाई बाजारों में एफएमसीजी, दूरसंचार, उपकरण, खुदरा, संपत्ति, फर्नीचर, सुरक्षा समाधान, कृषि उत्पाद, बी2बी, प्रीमियम ब्यूटी केयर, ऑटो, स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

श्री कुमार प्रणेश, क्षेत्रीय प्रमुख, आईटीसी

praneshitc@yahoo.in

श्री कुमार प्रणेश कृषि-व्यवसाय प्रभाग के क्षेत्रीय प्रमुख (एनई) हैं। उन्हें सेल्स, सप्लाई चेन और सोर्सिंग में 21 साल का अनुभव है। आईटीसी अपनी ईचौपाल पहल के माध्यम से किसानों के लाभ के लिए आईटी प्रगति को अपनाने वाले पहले संगठनों में से एक है। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, उन्होंने यूपी, एमपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार राज्य में किसानों के लिए बाजार संपर्क और जीवन शैली में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मीनांगडी पंचायत, केरल के प्रतिनिधि

केरल के वायनाड जिले की मीनांगडी ग्राम पंचायत कार्बन तटस्थता की दिशा में प्रयासों का नेतृत्व कर रही है और ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत स्तर पर कई संस्थागत उपाय किए हैं।

सुश्री मनीषा चौधरी, यूएनईपी

manisha.choudhary@un.org

सुश्री मनीषा चौधरी, राष्ट्रीय समन्वयक, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी (पेज) भारत, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भारत कार्यालय: सुश्री मनीषा चौधरी भारत में संयुक्त राष्ट्र

पर्यावरण कार्यक्रम के साथ साझेदारी पर कार्यक्रम हेतु हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में काम कर रही हैं। यूएनईपी में शामिल होने से पहले, वह भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ जैव विविधता वित्त के क्षेत्र में काम कर रही थी।

डॉ इंदु भूषण, पूर्व सीईओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

श्री इंदु भूषण राजस्थान कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन) कार्यक्रमों के पूर्व सीईओ हैं, जिनका उद्देश्य देश की कम आय वाली आबादी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। वह एशियाई विकास बैंक के पूर्व महानिदेशक भी हैं। श्री भूषण को जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ से ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड मिला, जहाँ वे एक छात्र थे।

श्री अमित सिंह, कार्यकारी निदेशक, डेलॉइट

asingh46@deloitte.com

श्री अमित सिंह डेलॉइट कंसल्टिंग के कार्यकारी निदेशक हैं। श्री अमित भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में एक कुशल नेता हैं, जिनके पास बड़ी डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं को वितरित करने में 20+ वर्षों का अनुभव है। श्री अमित ने भारत की विशिष्ट पहचान परियोजना, पंचायत राज मंत्रालय के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना, भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के स्वचालन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के राष्ट्रीय भंडार आदि जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर काम किया है।

श्री **श्यामल सांतरा, ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन**

shyamal@trif.in

श्यामल संतरा लीड-पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के रूप में कार्यरत हैं। श्यामल को ग्रामीण भारत को बदलने के लिए स्केलेबल समाधानों को संचालित करने और चलाने के दौरान सामुदायिक नेतृत्व का पोषण करने का व्यापक अनुभव है। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पहलों - एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) और XV-FC हेल्थ सेक्टर ग्रांट के साथ अद्वितीय जुड़ाव रखने के बाद, वह उस कोर टीम में थे जिसने पहले 'ममता वाहन' को तैयार किया था; पिछले 10 वर्षों में फ्रंटलाइन

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों और पंचायती राज संस्थानों के एक समूह के जरिये 2 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं के परिवहन की सुविधा प्रदान की और 'झारखंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन (JIDHAN) प्रोग्राम' का सह-निर्माण और नेतृत्व किया।

श्री लोक रंजन, सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय secydoner@nic.in

श्री लोक रंजन त्रिपुरा कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीएनईआर) में भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अतीत में, उन्होंने भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। अपनी पिछली पोस्टिंग में, वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार में अपर सचिव और स्थापना अधिकारी और निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी के प्रभारी थे। उन्होंने पहले वित्त विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, आदि में वरिष्ठ पदों पर भी कार्य किया था।

निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश panchraj@nic.in

श्री अनुज कुमार झा निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार